RNI No. 38189/72

पोस्टिंग - प्रति बुधवार

डाक पंजीयन MP/IDC/58/2024-2026

संस्थापक - स्व. श्री जीवन साहू

युग प्रभात

प्रति गुरुवार | साप्ताहिक | राष्ट्रीय समाचार पत्र | हर कदम पर नए युग के साथ

वर्ष - 55, अंक - 23 | इंदौर, 12 से 18 फरवरी 2026 | पृष्ठ-8, कीमत 3 रुपए

अमेरिका-ईरान के बीच परमाणु वार्ता शुरु चिंतित नेतन्याहू करेंगे वाशिंगटन का दौरा

● तेलअवीव।

ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता शुरू होते ही इजरायल की चिंता बढ़ गई है। इसी कड़ी में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुधवार, 11 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। इस अहम बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

इजराइली पीएम नेतन्याहू की यह यात्रा तब हो रही है, जब अमेरिका और ईरान बीते एक महीने से तनाव कम करने के प्रयासों में जुटे हैं। ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों ने ओमान की राजधानी मस्कट में अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता की थी। संकेत मिले हैं कि दोनों देश

अगले सप्ताह फिर से बातचीत की मेज पर बैठ सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि बातचीत सकारात्मक रही है, जबकि ईरान ने अपने रुख को लेकर सतर्क बयान दिया है।

वहीं अब इजरायल को आशंका है कि अमेरिका कहीं ईरान के साथ ऐसा समझौता न कर ले, जिसमें उसके सुरक्षा हितों की अनदेखी हो जाए। इस बात से चिंतित नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी भी संभावित समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक और उसके सहयोगी गुटों जैसे हिज़्बुल्लाह और अन्य क्षेत्रीय संगठनों को समर्थन देने पर प्रतिबंध जैसी शर्तें जरूर शामिल हों। इजरायल का दबाव है कि अमेरिका इन मुद्दों को बातचीत से बाहर न रखे।

गौरतलब है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हालिया महीनों में कई बार मुलाकात हो चुकी है। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात दिसंबर में हुई थी। इस बीच ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी देते रहे हैं कि यदि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करता, तो सैन्य कार्रवाई भी एक विकल्प हो सकता है। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि वह अपने मिसाइल कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार नहीं है।

एसआईटी ने मेरी यात्रा के सिलसिले में कभी सवाल नहीं किया : गोगोई

● नई दिल्ली।

विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बीच तकरार जारी है। पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता ने सीएम सरमा पर पलटवार किया।

सोमवार को उन्होंने कहा कि असम के सीएम ने एसआईटी रिपोर्ट को 6 महीने तक दबाए रखा क्योंकि इसमें मेरे पाकिस्तान कनेक्शन के आरोपों को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। गुवाहाटी में कांग्रेस नेता

गौरव गोगोई ने कहा कि पुलिस को असम के सीएम द्वारा एक खास समुदाय को निशाना बनाने और सोशल मीडिया पर खराब वीडियो शेयर करने पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। मेरे नाबालिग बच्चों पर की गई टिप्पणियों के लिए असम के सीएम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरी पत्नी काम के सिलसिले में पाकिस्तान गई थी, मैं 2013 में 10 दिन की यात्रा पर उसके साथ गया था। एसआईटी ने मुझसे 2013 में 10 दिन की पाकिस्तान यात्रा के बारे में कभी सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि रविवार को 2.5 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए।

बाबा सिद्दीकी हत्या मामले के आरोपी आकाशदीप को मिली सशर्त जमानत

● मुंबई।

कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार 9 फरवरी को इस केस के आरोपी आकाशदीप करज सिंह को सशर्त जमानत दी है। आकाशदीप इस मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है। न्यायमूर्ति नीला गोखले की एकल पीठ ने जमानत देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक आरोपी मुंबई नहीं छोड़ेगा। बता दें कि 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी (66) की उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात को तीन हमलावरों ने अंजाम दिया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में पंजाब निवासी आकाशदीप करज सिंह (22) को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया था।

इसरो ने लैंडिग साइट तलाशी, चंद्रमा के साउथ पोल पर मॉन्स माउटन पहाड़ पर उतरेगा चंद्रयान-4

● बेंगलुरु।

इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए चंद्रमा के साउथ पोल के पास एक लैंडिंग साइट तलाश ली है। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से मिली तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने मॉन्स माउटन क्षेत्र को लैंडिंग के लिए सबसे सही बताया है। मॉन्स माउटन, चंद्रमा के साउथ पोल के पास स्थित करीब 6,000 मीटर ऊंचा पहाड़ है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक यह इलाका इसलिए भी अहम है, क्योंकि यहां लंबे समय तक सूर्य की रोशनी मिलती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में वॉटर आइस मौजूद होने की संभावना भी जताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इस स्टडी को लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। लैंडिंग साइट तय करने के लिए चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर लगे ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरे की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। यह कैमरा चंद्र सतह को करीब 32 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल के रेजोल्यूशन में दिखाता है। इससे छोटे क्रेटर, पत्थर, ढलान और सतह की बनावट साफ नजर आती है, जिससे लैंडिंग के लिए खतरनाक इलाकों की पहचान पहले ही हो जाती है। 2104 करोड़ रुपए के इस मिशन में चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। मिशन में दो अलग-अलग रॉकेट का इस्तेमाल होगा।

अतिरिक्त टैरिफ हटाकर ट्रंप ने सख्त निगरानी तंत्र भारत पर लागू किया!

● नई दिल्ली।

रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगे 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ हट गए हैं। अंतरिम व?यापार समझौते के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी किए हैं। इसमें भारत को तत्काल यह राहत दी गई है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इस राहत से कहीं ज?यादा महत्वपूर्ण वहां सख्त निगरानी तंत्र है जो इसके साथ आया है। एक जियो रणनीतिकार ने इस लेकर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में उन?होंने कहा कि यह आदेश अमेरिकी वाणिज्य मंत्री को भारत के तेल स्रोत को ट्रैक करने का काम सौंपता है। इससे एक?शन के लिए एक साफ ट्रिगर बनता है। ट्रंप के ऑर्डर सशर्त हैं। इसका मतलब है कि शर्त टूटने पर 25 प्रतिशत टैरिफ की वापसी हो सकती हैं। जानकार ने लिखा, रूसी तेल पर ट्रंप के कार्यकारी आदेश में असली चुभन इसके निगरानी जनादेश में निहित है।

यह औपचारिक रूप से वाणिज्य मंत्री को भारतीय तेल आयात पर नजर रखने का काम सौंपता है जो स्पष्ट ट्रिगर बनाता है। यह पता चलने पर कि भारत ने सीधे या परोक्ष रूप से रूसी तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है, 25 प्रतिशत अतिरिक्त (दंडात्मक) टैरिफ वापस लागू हो सकता है। जानकार ने चेतावनी दी कि अप्रत्यक्ष रूप से शब्द का समावेश प्रवर्तन के दायरे को काफी हद तक बढ़ा देता है। जानकार ने बताया कि रियायती रूसी यूराल क्रूड को बाजार-मूल्य वाले अमेरिकी तेल से बदलना भारत के तेल आयात बिल में सालाना 4 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी कर सकता है। यह लंबी परिवहन दूरी के कारण और भी महंगा होगा है। उन्होंने कहा, वॉशिंगटन का इरादा साफ है... भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ज्यादा महंगा और भौगोलिक रूप से दूर सप्लायर अमेरिका से जोड़ना। अमेरिका ने कहा है कि भारत ने सीधे या परोक्ष रूप से रूसी तेल का आयात बंद करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। इस कदम से वॉशिंगटन ने पिछले अगस्त में

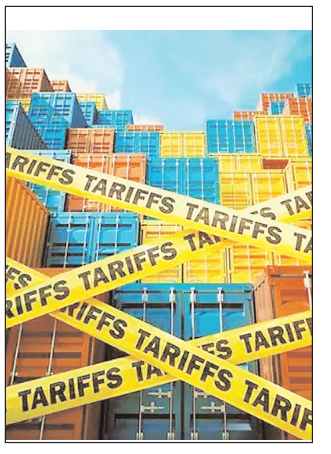

भारतीय सामानों पर लगाए गए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ को हटाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी कार्यकारी आदेश के अनुसार, भारत ने अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए अमेरिका के साथ एक ढांचे के लिए भी प्रतिबद्धता जाहिर की है। हालांकि, ट्रंप ने साफ किया है कि टैरिफ रोलबैक सशर्त है। रणनीतिकार ने बताया कि कार्यकारी आदेश में अमेरिका भारत के तेल स्रोत पर बारीकी से नजर रखेगा। उन्होंने कहा, वाणिज्य मंत्री, राज्य मंत्री, वित्त मंत्री और किसी भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ समन्वय में जिसे वाणिज्य मंत्री उचित समझता है, यह निगरानी करेगा कि क्या भारत सीधे या परोक्ष रूप से रूसी संघ के तेल का आयात फिर से शुरू करता है, जैसा कि कार्यकारी आदेश 14329 की धारा 7 में परिभाषित है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से एक निर्धारण आगे की कार्रवाई को ट्रिगर कर सकता है।

अगर वाणिज्य मंत्री को पता चलता है कि भारत ने सीधे या परोक्ष रूप से रूसी संघ के तेल का आयात फिर से शुरू किया है, तब राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, गृह मंत्री, अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक, आर्थिक नीति के लिए राष्ट्रपति के सहायक और व्यापार और विनिर्माण के लिए राष्ट्रपति के सहायक और वरिष्ठ सलाहकार के साथ परामर्श में यह सिफारिश करेगा कि क्या और किस हद तक मुझे भारत के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई करनी चाहिए।

इन्दौर मेट्रो के लिए कान्ह नदी के नीचे बनेगी 100 फीट की सुरंग, खुदाई शुरू

इंदौर । शहर के बहुप्रतीक्षित मेट्रो प्रोजेक्ट ने एक और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर लिया है। शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली कान्ह नदी के नीचे से मेट्रो गुजारने के लिए सुरंग की खुदाई का काम शुरू हो गया है। यह 100 फीट लंबा हिस्सा पूरे मेट्रो कॉरिडोर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जहां ट्रेन नदी की सतह से लगभग 50 फीट नीचे से गुजरेगी। इस काम के लिए शिवाजी मार्केट स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के पीछे खुदाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए पार्किंग के कुछ हिस्से को तोड़ा भी गया है। यहीं से सुरंग रामबाग ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज के बीच से होते हुए राजवाड़ा क्षेत्र की ओर बढ़ेगी।

राजवाड़ा स्टेशन का बदला स्थान पहले मेट्रो रूट पर राजवाड़ा में एक स्टेशन प्रस्तावित था, लेकिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की आपत्ति के बाद इसमें बदलाव किया गया। अब यह स्टेशन राजवाड़ा के बजाय सदर बाजार क्षेत्र में बनाया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के बीच बंगाली चौराहा से राजवाड़ा तक के रूट पर सहमति बन चुकी है, जिससे काम में तेजी आई है।

एयरपोर्ट पर भी अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी कान्ह नदी के अलावा, इंदौर एयरपोर्ट के पास भी मेट्रो के लिए एक अंडरग्राउंड टनल बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर आए बिना सीधे मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाना है। मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट परिसर से करीब 200 मीटर की दूरी पर बिजासन मंदिर जाने वाली सड़क के पास बनाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट के आगमन और प्रस्थान गेट के सामने एस्केलेटर लगाए जाएंगे, जो उन्हें सीधे स्टेशन की अंडरग्राउंड टनल तक ले जाएंगे।

इस हिस्से पर भी काम शुरू हो चुका है, जिससे भविष्य में हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रोजेक्ट की प्रगति और लागत इंदौर मेट्रो के पहले चरण में कुल 31 किलोमीटर लंबे रूट का निर्माण हो रहा है, जिस पर 29 स्टेशन बनाए जाएंगे। एक सामान्य स्टेशन के निर्माण पर करीब 58 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है, जबकि अंडरग्राउंड स्टेशनों की लागत काफी अधिक है।इस रूट पर कुल 8 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे, जिनमें से प्रत्येक के निर्माण पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे। फिलहाल, अधिकारियों का पूरा ध्यान 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर है। इस हिस्से में ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि अगले महीने तक इसका व्यावसायिक संचालन भी शुरू हो जाएगा। गांधी नगर डिपो से रेडिसन चौराहे तक का रूट लगभग तैयार है।

फर्नीचर सहित अन्य संसाधनों को लेकर प्राचार्यों की बैठक

इंदौर । स्थानीय मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा संचालन नोडल केंद्र पर इंदौर जिले के सभी प्राचार्य की एक विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में आरंभ होने जा रही 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में फर्नीचर सहित अन्य संसाधन जुटाने के संदर्भ में चर्चा भी की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए।

जैसा कि सभी जानते हैं आगामी 10 फरवरी से हाई स्कूल की और 13 फरवरी से हायर सेकेंडरी बोर्ड की मुख्य वार्षिक परीक्षाएं आरंभ होने जा रही है। इसकी सभी जरूरी अहर्ताएं पूरी कर दी गई है ।एक और जहां केंद्र अध्यक्ष तय कर लिए गए हैं तो दूसरी तरफ सहायक केंद्र अध्यक्षों को भी नियुक्त कर दिया गया है इसके अलावा परीक्षार्थियों को उनके प्रश्न पत्र प्रवेश पत्र वितरित कर दिए गए हैं तो प्राचार्यों को भी अहम बैठक में संसाधन जुटाने के उन्हें दिशा निर्देश दे दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर साफ-सफाई पेयजल फर्नीचर बिजली आपूर्ति व्यवस्था सहित तमाम बिंदुओं पर इस अहम बैठक में चर्चा हुई कुछ प्राचार्य ने कर्मचारियों की कमी खास तौर पर प्यून वर्ग के कर्मचारियों के अभाव की बात कही। इस पर अन्य स्कूलों में पदस्थ प्यून की ड्यूटी परीक्षा मामले में लगाने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर साफ सफाई व्यवस्था पेयजल व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं इधर कलेक्टर के निर्देश के बाद सभी परीक्षा केंद्रों के अंतर्गत फीडर और डीपी इंचार्ज को निर्देशित कर दिया गया है की परीक्षा के दौरान विद्युत कटौती नहीं होना चाहिए, बल्कि सतत विद्युत आपूर्ति होना चाहिए। बैठक में इंदौर महू देपालपुर सांवेर सहित सभी ब्लॉकों के प्राचार्य संकुल अधिकारी मौजूद थे।

भक्तिभाव से शबरी मैया ने पूरे वनवासी समाज का बढ़ाया मानः मुख्यमंत्री

इंदौर । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जिन्होंने निःशब्द रहकर अपनी पुण्य भावनाओं को अमर शब्द दे दिए, ऐसी शबरी मैया को पूरे मध्यप्रदेश की ओर से नमन है, वंदन है। जिनके जूठे बेर खाकर भगवान श्री राम भी भक्तिभाव से धन्य हो गये उस माता शबरी की महिमा कौन नहीं जानता। भगवान को बेर भी भेंट देने से पहले खुद बेर का मीठापन जांच लेना भक्ति का उत्कर्ष है।

यह प्रसंग हमें बताता है कि भगवान भक्त की आराधना पद्धति के नहीं, बल्कि उसके मन के भावों के भूखे होते हैं। व्यक्ति का मूल्य उसके हृदय की पवित्रता से तय होता है, जन्म से नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल समाज की कुल देवी शबरी मैया हम सबके लिए सदैव आराध्य हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। उन्होंने अपने चरित्र एवं सत्कर्मों से पूरे वनवासी और जनजातीय समाज का मान बढ़ाया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को शहडोल जिले की ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गंधिया स्थित सीतामढ़ी धाम में माता शबरी जयंती पर आयोजित जनजातीय हितग्राही सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सीतामढ़ी परिसर में शबरी मैया की एक सुंदर प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्राम गंधिया से शहडोल जिले के

लिए 747 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत वाले 139 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 79 कार्यों का लोकार्पण तथा 134 करोड़ रूपए से अधिक लागत के 60 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय वर्ग का समग्र कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में है। प्रदेश में पीएम जन-मन योजना के अंतर्गत 98 करोड़ 30 लाख रुपए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 401.56 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जा चुका है। हमारी सरकार ने जनजातीय समाज के नायकों की गौरव गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है।

चुनावी व्यवस्था को परीक्षा व्यवस्था में भी लागू कर दिया, राज्य शिक्षा मंत्रालय ने

नई व्यवस्था ने बढ़ाई पारदर्शिता, एहतियाति व्यवस्था की सर्वत्र चर्चा

इंदौर । यह पहला अवसर है जब राज्य शिक्षा मंत्रालय ने भी चुनावी मतदान सामग्री सुरक्षा व्यवस्था को अपनाया है और चार स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका और परीक्षा संबंधी अन्य सामग्री थाने पहुंची और वहां से अब परीक्षा केंद्रों दो तक पहुंचें। आमतौर पर होता यह था कि मालव कन्या विद्यालय से एक जवान या दो जवान की उपस्थिति में प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका और अन्य सामग्री थाने ले जाई जाती थी लेकिन इस बार इसमें चार स्तरीय लेयर व्यवस्था लागू कर दी गई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से इस बार पूरे मध्य प्रदेश में एक नए प्रकार की व्यवस्था को लागू किया है इसके अंतर्गत चार थाने के जवान एक साथ चारों थाने जाएंगे और वहां केंद्र अध्यक्ष सहायक केंद्र अध्यक्ष केंद्र अध्यक्ष की मौजूदगी में उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र और अन्य सामग्री पंचनामे के पश्चात थाने के रिकॉर्ड रूम में रखवाई।

अब तक यह होता था कि संबंधित परीक्षा केंद्र के अंतर्गत पडने वाले थाने में जिस जवान की ड्यूटी वितरण केंद्र पर लगाई जाती थी वह केंद्र अध्यक्ष सहायक केंद्र अध्यक्ष के साथ थाने पहुंचकर सामग्री जमा कर दिया करता था लेकिन पहली बार थाने और चार परीक्षा केंद्रों के बीच रूट चार्ट व्यवस्था लागू की गई है । ताकि व्यवस्था मतदान सामग्री लाने ले जाने में की जाती थी अब एक साथ चार गार्ड, चार परीक्षा केंद्र अध्यक्ष ,सहायक परीक्षा केंद्र अध्यक्ष एक दूसरे के केंद्रों के अंतर्गत पड़ने वाले थाने पहुंचें और वहां उन्होंने यह सामग्री जमा करवाई।

सूत्रों का कहना है कि यह इस बार आंतरिक और नई व्यवस्था लागू की गई है ।इससे पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही और यह चुनावी मतदान सामग्री व्यवस्था के समक्ष है।

यह देखने में आता था कि देश के अंदर राज्यों में सिंगल और विकेंद्रीकृत व्यवस्था होने के कारण कई बार पेपर आउट होने जैसे मामले भी सामने आ जाया करते थे लेकिन इस बार मध्य प्रदेश शासन ने और खास तौर पर राज्य शिक्षा मंत्रालय ने इस नई व्यवस्था को लागू किया है ताकि परीक्षाओं को लेकर कहीं कोई व्यवधान भी ना हो और प्रश्न पत्र आउट होने जैसी गूंज से भी नगण्य हो जाए।

राज्य शिक्षा मंत्रालय ने डीपीआई, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्यालय के अधिकारियों के मार्गदर्शन और निगरानी में इस नई व्यवस्था को लागू किया है इस नई व्यवस्था की शिक्षा जगत में व्यापक चर्चाएं हैं।

बैरसिया में 721 लाख रुपये के 36 विकास कार्यों की दी सौगात

इंदौर । पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को विकास की महत्वपूर्ण सौगात प्रदान की। उन्होंने लगभग सात करोड़21 लाख रुपये की लागत से निर्मित एवं प्रस्तावित 36 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इन कार्यों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण सुविधाओं के विस्तार तथा जनकल्याण से जुड़े अनेक कार्य सम्मिलित हैं, जो क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा देंगे। विकास कार्यों के शुभारंभ के उपरांत मंत्री श्री पटेल ने 'विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए उपस्थित नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'गारंटी' का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। यह अभियान ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम के दौरान स्वसहायता समूहों से जुड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं तथा मातृशक्ति के साथ मंत्री श्री पटेल ने सीधा संवाद किया। उन्होंने समूहों को उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न वित्तीय प्रावधानों, तकनीकी सहयोग तथा विपणन संबंधी अवसरों की जानकारी देते हुए बताया कि रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि का पारदर्शी एवं सही उपयोग कर महिलाएँ आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

नर्मदापुरम।

किशोर बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के उद्देश्य से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उमंग स्कूल हेल्थ एंड वैलनेस कार्यक्रम संचालित हो रहा है। किशोर बच्चों को उनकी समस्याओं की पहचान कराना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उनका सर्वांगीण विकास करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। वर्तमान में उमंग स्कूल हेल्थ एंड वैलनेस कार्यक्रम हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में चलाया जा रहा है। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शाला में भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से इस कार्यक्रम में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के पहले चरण में नर्मदापुरम तथा माखन नगर के शिक्षक शामिल हुए। इसमें दोनों ब्लॉक की प्रत्येक सरकारी स्कूल से माध्यमिक कक्षा के शिक्षक शामिल हुए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। जिसके माध्यम से जिले के सभी माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को हेल्थ एंड वैलनेस एंबेसेडर के रूप में प्रशिक्षित किया जा? रहा है।

उमंग है तो जिंदगी में रंग है जैसी भावना को ध्यान में रखते हुए यह शिक्षक अपने विद्यालय के किशोर बच्चों को उनका सर्वांगीण विकास करने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। प्रशिक्षकों ने कक्षावार जीवन कौशल शिक्षा संबंधी मॉड्यूल के आधार पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के दौरान राजेंद्र कुमार ठाकुर डीआरजी पिपरिया, सोनू जैन डीआरजी सिवनी मालवा, हेमंत पटेल डीआरजी बनखेड़ी, नर्मदापुरम से कला मीणा, जितेंद्र शर्मा ने प्रशिक्षक की भूमिका निभाई।

समाज में शिक्षक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण- डीपीसी राजेश जायसवाल

प्रथम बैच के समापन कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शिक्षा विभाग से डीपीसी राजेश जायसवाल उपस्थित हुए। आपने विद्यार्थियों के हित में चलाए जा रहे उमंग कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे उनके जीवन में बेहद लाभकारी बताया। आपने कहा कि विद्यार्थी के साथ-साथ समाज के विकास में भी शिक्षक की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम सभी को सामूहिक प्रयास के माध्यम से शिक्षा के स्तर को तो बढ़ाना ही है,

साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भी मिलजुल कर कार्य करना है। इस अवसर पर एसीपी विनोद केरकेट्टा, आरकेएसके जिला समन्वयक कविता साल्वे, प्रशिक्षक, समस्त शिक्षक उपस्थित रहे। समापन सत्र का संचालन उमंग स्वास्थ्य केंद्र के परामर्शदाता ईश्वर विश्नोई ने किया।

प्रशिक्षण के दौरान आरकेएसके की जिला समन्वयक कविता साल्वे का निरंतर मार्गदर्शन मिला। आपने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए 10 से 19 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के परामर्श हेतु संचालित उमंग स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानकारी दी। मनहित ऐप, टेली मानस हेल्पलाइन, जस्ट आस्क चैटबाट के प्रयोग संबंधी जानकारी विस्तार से दी गई। आयोजक के रूप में संपूर्ण कार्यक्रम की संचालन व्यवस्था जन मंगल संस्थान की ओर से की गई। संस्था की ओर से परियोजना प्रभारी कपिल चौरसिया के मार्गदर्शन में जिला अस्पताल के परामर्शदाता शुभम संतोरे, सिवनी मालवा से परामर्शदाता ईश्वर विश्नोई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आधा दर्जन फैक्ट्रियों पर फिर पौने दो लाख का जुर्माना सील होगी फैक्ट्रियां

इन्दौर । पिछले कई दिनों से सांवेर रोड के अलग अलग सेक्टरों में नगर निगम द्वारा कार्रवाई कर विभिन्न फैक्ट्रियों और उद्योगिक ईकाइयों पर जहरीला पानी नाले में छोडने के मामले को लेकर चालानी कार्रवाइयां की जा रही हैं। निगम ने कल भी आधा दर्जन फैक्ट्रियों पर चालानी कार्रवाइयां की और पौने दो लाख रूपये जुर्माना वसूला। अफसरों का कहना है कि अब फैक्ट्रि संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी और जहरीला पानी बहाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा और इसके लिए अलग अलग सेक्टरों में मुनादी भी शुरू कर दी गई है।

नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर नगर निगम की टीमो द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण एवं चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते झोन क्रमांक 17 और 3 के अंतर्गत सांवेर रोड एवं पोलो ग्राउंड स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में नालों में गंदगी एवं जहरीला पानी छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक सांवेर रोड की फैक्ट्री ललित नमकीन, मेघा पॉलिमर, गीतिका प्लास्टिक, उषा ऑर्गेनिक और सायनों फार्मा कंपनी, कोहिनूर इलास्टिक आदि फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर 1 लाख 80 हजार का जुर्माना वसूला गया और साथ ही फैक्ट्री संचालकों को चेतावनी दी गई कि वे जहरीले पानी के निपटान के लिए फैक्ट्री परिसर में ही ईटीपी संयंत्र लगाए और पानी का निपटान करें। कार्रवाई के दौरान झोनल अधिकारी राज ठाकुर, सीएसआई राजेंद्र बेगा और ड्रेनेज विभाग की टीम उपस्थित रही।

अधिकारियों के मुताबिक अब निगम द्वारा सांवेर रोड और पोलो ग्राउंड के अलग अलग सेक्टरों में निगम की पीली जीपों से मुनादी कराई जा रही है कि किसी भी फैक्ट्री का पानी नाले अथवा सीवरेज में छोड़ा गया तो संबंधित फैक्ट्रियों को सील करने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाएगी। अफसरों का कहना है कि लगातार 4 से 5 दिनों तक क्षेत्र में मुनादी की जाएगी और उसके बाद फैक्ट्रियों पर ताले डालने की कार्रवाई भी शुरू होगी।

संगठन की मजबूती पर जोर : कांग्रेस ने निचले स्तर तक गठित की कमेटियां

भोपाल । प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जिला इकाइयों पर सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने भोपाल संभाग के सभी जिला अध्यक्षों को साफ निर्देश दिए हैं कि पंचायत और वार्ड स्तर की कमेटियों का गठन तय समय सीमा में पूरा किया जाए। प्रदेश कार्यालय इंदिरा भवन में रविवार को हुई बैठक में कहा गया कि सभी जिला अध्यक्ष 20 फरवरी तक पंचायत और वार्ड कमेटियों की सूची संगठन को सौंपें। जिन जिलों ने अब तक मंडल कमेटियों की सूची नहीं भेजी है, उन्हें 5 दिन के भीतर सूची तैयार कर जमा करने का निर्देश दिया गया है।

बैठक में संगठनात्मक ढांचे को लेकर बड़ा फैसला भी लिया गया। जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी कार्यकारिणी का आकार घटाएं। जहां पहले जिला कार्यकारिणी में करीब 70 सदस्य होते थे, अब उन्हें अधिकतम 35 सदस्यों तक सीमित करने को कहा गया है। प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि बड़ी कार्यकारिणी नहीं, बल्कि सक्रिय और प्रभावी टीम चाहिए।

प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी हरीश चौधरी ने जिला नेताओं से कहा कि संगठन विस्तार के साथ-साथ बीजेपी सरकार की नाकामियों को आम जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष को शहर की मंडल कमेटियों का गठन जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।

संगठन मजबूत करने पर मंथन

बैठक में ग्राम, वार्ड और पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने, आगामी योजनाओं और चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेतृत्व का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने और बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत करने पर रहा। बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, AICC सचिव संजय दत्त, पूर्व विधायक रवि जोशी, भोपाल जिला अध्यक्ष (शहर) प्रवीण सक्सेना, भोपाल जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) अनोखी पटेल, विधानसभा प्रभारी और सभी ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हुए।

सच्चा वादा-पक्का काम ही राज्य सरकार की पहचान है : मुख्यमंत्री

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सच्चा वादा-पक्का काम ही राज्य सरकार की पहचान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय भाई-बहनों के सर्वांगीण विकास में जुटी है। जनजातीय भाई-बहनों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माता शबरी जयंती की शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि निष्कपट भक्ति, समर्पण और साधना की सर्वोच्च प्रतीक शबरी मैया ने सारा जीवन रघुवर की प्रतीक्षा की। प्रेम में समर्पित इस प्रतीक्षा का फल केवल माता शबरी को ही नहीं मिला बल्कि स्वयं भगवान श्री राम को भी मिला। मनुष्य से मनुष्य का प्रेम ही सनातन संस्कृति की विशेषता है। भगवान श्रीराम और माता शबरी का प्रेम बताता है कि हमारे समाज में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शहडोल जिले में धनपुरी नगर पालिका द्वारा 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए वाटर पार्क के लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज रविवार को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का साफा तथा गजमाला पहनाकर अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री श्री दिलीप जयसवाल तथा सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह विशेष रूप से उपस्थित।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गीता भवन निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि इसके बन जाने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाइब्रेरी और कोचिंग जैसी शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में सुविधा होगी।

आईसीएसई स्कूल से निष्कासित छात्र पर स्पष्ट की दखल, सरकार सहित सभी पक्षों को दिया नोटिस

इंदौर । एक निजी आईसीएसई स्कूल से निकाले गए 14 वर्षीय छात्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कड़ा रुख अपनाया है. इसमें सरकार के स्कूल विभाग के प्रिंसिपल सेकेट्री, आईसीएसई बोर्ड, लिटिल वंडर्स कॉन्वेंट स्कूल, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंदौर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है।

अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से 13 फरवरी 2026 तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि छात्र को परीक्षा में शामिल कराने की व्यवहारिक व्यवस्था कैसे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना और उज्जल भुयान की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बच्चे की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए और यह मामला केवल अनुशासन का नहीं, बल्कि छात्र के शैक्षणिक भविष्य से सीधे जुड़ा है। इसलिए त्वरित समाधान आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी प्राधिकरण अपने-अपने स्तर पर यह बताएं कि छात्र को बोर्ड परीक्षा में शामिल कराने का तरीका क्या होगा? किस संस्था की क्या जिम्मेदारी होगी? शिक्षा जारी रखने के लिए कौन-सी वैकल्पिक व्यवस्था संभव है? अदालत ने संकेत दिए कि समाधान ऐसा हो जिससे छात्र का शैक्षणिक वर्ष और परीक्षा प्रभावित न हों। दरअसल यह पूरा प्रकरण एक 14 वर्षीय छात्र से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इंस्टाग्राम पर एक निजी अकाउंट बनाया और शिक्षकों के खिलाफ आपत्तिजनक मीम्स साझा किए।

स्कूल प्रबंधन ने इस आधार पर छात्र को आगे की कक्षाओं से वंचित निष्कासित कर दिया। उल्लेखनीय है इंदौर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद याची ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कथित कदाचार की तुलना में दी गई सजा असंगत और अनुपातहीन है याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निपुण सक्सेना ने दलील दी कि कथित कदाचार की तुलना में दी गई सजा पूरी तरह असंगत और अनुपातहीन है। उन्होंने कहा कि आरोप सिद्ध

सम्पादकीय

गड्ढों वाली व्यवस्था और खतरे में पड़ता जीवन

गड्ढों में गिरी व्यवस्था में समाप्त होता जीवन आज के भारत की एक ऐसी विडंबना बन चुका है, जिसे देखकर मन भीतर तक सिहर उठता है। नोएडा में कार सवार युवा इंजीनियर की गड्ढे में गिरकर मौत का दर्द अभी समाज के मन से उतरा भी नहीं था कि दिल्ली में बाइक सवार युवक की जान एक खुले गड्ढे ने लील ली। दोनों घटनाओं में समानता यह है कि गड्ढे प्रशासन द्वारा विकास या मरम्मत के नाम पर खोदे गए थे और दोनों जगह न तो कोई बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड, न रोशनी की व्यवस्था। मानो व्यवस्था ने पहले गड्ढा खोदा और फिर निश्चिंत होकर वहां से हट गई कि अब जो होगा, वह नागरिक की किस्मत है। यही वह सोच है जो किसी भी समाज को भीतर से खोखला कर देती है। प्रश्न यह नहीं है कि गड्ढे क्यों खोदे गए, प्रश्न यह है कि गड्ढे खोदकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का अधिकार प्रशासन को किसने दिया। क्या विकास का अर्थ यह हो गया है कि सड़कों पर चलते हुए हर नागरिक अपनी जान हथेली पर रखे। क्या शहरों की चमक-दमक और बड़े-बड़े दावों के बीच आम आदमी का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि उसकी मौत पर सिर्फ एक खबर छप जाए, दो दिन बहस हो और फिर सब कुछ सामान्य हो जाए। यह सामान्य हो जाना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब मौतें सामान्य लगने लगें, तब व्यवस्था की संवेदनशीलता मर चुकी होती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड्ढा हो या नोएडा की किसी एजेंसी का, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया हर बार एक जैसी रहती है। अफसर निलंबित कर दिए जाते हैं, जांच समितियां बना दी जाती हैं, 24 या 48 घंटे में रिपोर्ट देने की घोषणा होती है और कुछ समय बाद वही फाइलें धूल फांकने लगती हैं। निलंबन और जांच अब समाधान नहीं, बल्कि एक औपचारिक रस्म बन गई है। सवाल यह है कि क्या निलंबन से मरे हुए बेटे लौट आते हैं, क्या जांच समितियों से टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। जब तक जवाबदेही केवल कागजों पर सिमटी रहेगी, तब तक गड्ढों में गिरती जिंदगियां यूं ही व्यवस्था का शिकार बनती रहेंगी। इस पूरी तस्वीर का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं कम से कम चर्चा में तो आती हैं, मीडिया सवाल तो उठाता है, लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में यही गड्ढे रोज जिंदगियां निगल रहे हैं और खबर तक नहीं बनते। वहां न कैमरा पहुंचता है, न कोई प्रतिनिधि, न कोई जांच समिति। वहां मौतें सिर्फ परिवारों की निजी त्रासदी बनकर रह जाती हैं। क्या नागरिक का मूल्य शहर के आकार से तय होगा। क्या महानगरों का नागरिक ज्यादा कीमती है और छोटे शहरों का नागरिक सस्ता। यह असमानता केवल संसाधनों की नहीं, बल्कि संवेदनाओं की भी है। हम एक ओर विकसित भारत, सशक्त भारत, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी सड़कों पर खुले गड्ढे हमें आईना दिखाते हैं। विकास की रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन यदि उस रफ्तार में सुरक्षा, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना नहीं जुड़ी, तो वह रफ्तार विनाश की ओर ही ले जाएगी। यह विडंबना ही है कि हम स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, लेकिन स्मार्ट बैरिकेडिंग, स्मार्ट चेतावनी और स्मार्ट जिम्मेदारी पर बात करना भूल जाते हैं। तकनीक के युग में भी एक साधारण चेतावनी बोर्ड लगाना हमारे तंत्र को याद नहीं रहता। दरअसल समस्या केवल लापरवाही की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें नागरिक को एक आंकड़ा समझ लिया गया है। फाइलों में वह एक केस नंबर है, सड़क पर वह एक बाधा और हादसे के बाद वह एक आंकड़ा। जब तक प्रशासन और शासन की दृष्टि में नागरिक का जीवन सर्वोपरि मूल्य नहीं बनेगा, तब तक हर नया गड्ढा एक नई मौत की संभावना बनकर खड़ा रहेगा।

सामाजिक न्याय हासिल करने की लम्बी यात्रा

रोहित वेम्यूला और अबेदा सलीम तड़वी की आत्महत्या के मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिकाओं और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या करने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक 16-पृष्ठीय दस्तावेज जारी किया जिसमें वे दिशानिर्देश थे जिन्हें उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाना था। इन दिशानिर्देशों का उद्धेश्य था छात्रों को अपमान या ऐसे नकारात्मक विचारों से बचाना जिनके चलते वे अपनी जान ले लेते हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस तरह की त्रासद और भयावह घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। राज्यसभा को प्रस्तुत की गई रपट ''सिग्नीफिकेंट स्टूडेंट सुइसिडस (2018-2023) में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में आईआईटी, आईआईएम और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थाओं में 98 छात्रों ने आत्महत्या की। हाशिए पर पड़े समुदायों में स्थिति अधिक चिंताजनक हैः केन्द्रीय संस्थानों में 2014 से 2021 के बीच आत्महत्या करने वाले कुल 122 छात्रों में से अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के थे। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों की संख्या में 2019 से 2024 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 118.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

इसके मद्देनजर यूजीसी की अनुशंसाएं एक ताजी हवा के झोंके की तरह हैं। लेकिन उत्तर भारत के कई स्थानों पर इनका विरोध किया गया, अधिकांशतः उच्च जातियों द्वारा जो संभवतः भाजपा की राजनीति के समर्थक थे। वे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए, जिसने आनन-फानन में यूजीसी के दिशानिर्देशों को लागू करने पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि इस तरह के कदमों से समाज बंटेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें अस्पष्ट बताते हुए कहा कि इनका बहुत आसानी से दुरूपयोग किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कानूनों के दुरूपयोग की संभावना हमेशा रहती है और जरूरी प्रावधान करके इसे रोका जा सकता है। तथ्य यह है कि इस तरह की घटनाओं की संख्या में 2019 से 2024 के बीच 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रोफेसर सतीश पांडे का तर्क है कि अतीत में जाति प्रथा के माध्यम से प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हुए पहले तो उच्च जातियों ने समाज में ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया और फिर वे जाति-विहीन समाज की बातें करने लगीं। प्रोफेसर अजंथ सुब्रमण्यम बताते हैं कि किस तरह जाति-विहीनता को योग्यता को सबसे अधिक तरजीह देने से जोड़ा गया और इसका उपयोग ऊंची जातियों ने तमिलनाडु में जम कर किया क्योंकि वहां का सबाल्टर्न वर्ग अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। मगर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिए जाने से ऊंची जातियों अब योग्यता की दुहाई देने की स्थिति में भी नहीं हैं।

भाजपा को केन्द्र में सत्तारूढ़ हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। ऊंची जातियां यह जानती हैं और यह अपेक्षा करती हैं कि यह सरकार 'उनकी पक्षधर' है और वह समाज के वंचित वर्गों के हित में उठाए जाने वाले हर सकारात्मक कदम को निष्प्रभावी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। इसकी एक मिसाल है उच्च शिक्षण संस्थाएं जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के लिए आरक्षित पद रिक्त हैं जबकि आवश्यकत योग्यता रखने वाले इन समुदायों के शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारा अनुभव यह रहा है कि यह सरकार सामान्यतः उच्च जातियों को संरक्षण देती है और इसके राज में वंचित वर्गों पर होने वाले अत्याचारो की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ दशकों में इन वर्गों की स्थिति बहुत खराब हुई है। कई आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सूचकांको से इसकी पुष्टि होती है। ''नेशनल कोएलेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग एससीज एंड एसटीज'' के प्रतिवेदन में दिए गए आंकड़ों से ज्ञात होत है कि अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों में 2021 में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021 में ऐसी सबसे अधिक घटनाएं उत्तरप्रदेश में हुई जो कुल घटनाओं का 25.82 प्रतिशत थीं। इसके बाद राजस्थान और मध्यप्रदेश 14.7 और 14.1 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

प्रतिवेदन भारत के सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र में व्याप्त सड़ांध की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इसमें हिन्दुत्व शक्तियों की विचारधारा और उनके द्वारा समाज के चिन्हित वर्गों के विरूद्ध की जा रही हिंसा के कारण उसमें हुई बढ़ोत्तरी पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। दलित ऐसा ही एक वर्ग है जिसे निशाना बनाया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी वर्ग की लड़ाई लंबे समय से जारी है। पहला कदम था यह सुनिश्चित करना कि उनके साथ समानतापूर्ण व्यवहार हो और वे उच्च जातियों के प्रतिरोध के बावजूद शिक्षा हासिल कर सकें। जोतिराव फुले का जीवन एवं संघर्ष इसका उदाहरण है कि मनुष्य होने के नाते वे जिन मूलभूत अधिकारों के हकदार थे, उन्हें हासिल करने में भी उच्च जातियों ने कितनी बाधाएं खड़ी कीं। बाबासाहेब अम्बेडकर ने यह संघर्ष जारी रखा और इसमें मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक जल स्त्रोतों तक पहुंच और अस्पृश्यता के विरोध जैसे मुद्दों को जोड़ा। राष्ट्रपिता ने अपने जीवन के कई वर्ष अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते हुए बिताए। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उनकी जान लेने का पहला प्रयास तब किया गया था जब उनका मुख्य संघर्ष अस्पृश्यता के उन्मूलन के खिलाफ चल रहा था और वे दलित उत्थान में जुटे हुए थे।

भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के विरूद्ध प्रावधान किए गए। उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की कई, हालांकि ओबीसी वर्ग के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस पर अमल आधे-अधूरे मन से किया गया और इन वर्गों के बहुत से लोग आवश्यक योग्यता के बावजूद नौकरियां हासिल करने से वंचित रहे।

आरक्षण लागू होने के बाद सन् 1980 आते-आते उच्च जातियों के एक वर्ग ने आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दिया। प्रोपेगेंडा यह चलाया गया कि आरक्षित वर्गों के कम काबिल उम्मीदवारों की वजह से उच्च जातियों के अधिक योग्य उम्मीदवारों को नौकरियां हासिल नहीं हो पा रही हैं। आरक्षित वर्ग के लोगों को 'सरकार का दामाद' कहा जाने लगा। ये भ्रांतियां समाज की व्यापक समझ का हिस्सा बन गईं। इन वर्गों के प्रति नफरत के चलते 1980 के दशक में उनके विरूद्ध हिंसा हुई - पहले सन् 1980 में फिर 1985 में।

आरक्षण के विरोध के लिए 'यूथ फॉर इक्यालिटी' जैसे समूह गठित हुए जिन्होंने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के खिलाफ कुलीन वर्गों के तर्कों को प्रचारित करने का काम किया। शिक्षण संस्थानों के परिसरों में भी इन वर्गों के खिलाफ नफरत का माहौल कायम हो गया जो अब बढ़ती आत्मघात की घटनाओं के रूप में साफ नजर आ रहा है। यह तर्क बेमानी है कि इन दिशानिर्देशों में उच्च जातियों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि आत्महत्या की ज्यादातर घटनाओं का संबंध अनुसूचित जाति / जनजाति / ओबीसी वर्गों के छात्रों से है। सन् 1990 में व्ही. पी. सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला उच्च जातियों के लिए एक जबरदस्त झटका था और इसका जबरदस्त विरोध हुआ। भाजपा ने अत्यंत कुटिलतापूर्वक इसका विरोध नहीं किया। उसने जनता का ध्यान इस मुद्दे से हटाने के लिए राम मंदिर निर्माण हेतु रथयात्रा शुरू की। इससे देश दहल गया, रथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले बहुत से स्थानों पर साम्प्रदायिक हिंसा हुई।

राम पुनियानी

ईमानदारी और आत्म सम्मान मानवीय जीवन के दो अनमोल हीरे मोती

सृष्टि रचनाकर्ता ने सृष्टि में मानवीय जीव की रचना कर उसके मस्तिष्क में बौद्धिक क्षमता रूपी खान का ऐसा अणखुट खजाना भर दिया है जिसमें अन्य 84 लाख़ योनियों को अलग रखा और यह जीव मानवीय योनि में जन्म लेकर अपने परिवार मोहल्ले समाज शहर के खूबसूरत माहौल में अपना बचपन बिताता है तो उसे हमारे बड़े बुजुर्ग ईश्वर अल्लाह का रूप मानतेहैं।

मैं यह मानता हूं और यह सर्वविदित भी है कि बच्चे झूठ, फरेब, बेईमानी इत्यादि अवगुणों से दूर स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण में अपना बालपन जीवन व्यतीत करते हैं जब बचपन से निकलकर बौद्धिक समझदारी में आते हैं उन्हें आकर्षित करने वाली अनेक चीजों में से एक धन है !जिसकी चाहना बल्यपन से निकलने पर ही आने लगती है और यहीं से कुदरत द्वारा दी गई अद्भुत अनमोल बौद्धिक क्षमता पर भ्रष्टाचार और लालच की नकारात्मक सोच हमला करती है जिसनें उसे ईमानदार और आत्म सम्मान रूपी अस्त्र से इन अवगुणों को काट दिया उसका संपूर्ण जीवन सफ़ल हो जाता है और जो इसके घेरे में आ गया वह परिवार कुल सहित दुखों का भागीदारी बन जाता है जिसका मूल कारण गलत स्त्रोतों से कमाया गया धन है !,इसलिए आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से भ्रष्टाचार फरेब अन्याय धोखे सहित गलत स्त्रोतों से कमाए गए धन के दुखद परिणामों और ईमानदारी आत्म सम्मान से लाभकारी परिवारों की चर्चा करेंगे।

साथियों बात अगर हम गलत स्त्रोतों से कमाए गए धन की करें तो श्लोकों में आया है। अन्यायोपार्जितं वित्तं दस वर्षाणि तिष्ठति।प्राप्ते चैकादशेवर्षे समूलं तद् विनश्यति।।

अर्थ- अन्याय या गलत तरीके से कमाया हुआ धन दस वर्षों तक रहता है। लेकिन ग्यारहवें वर्ष वह मूलधन सहित नष्ट हो जाता है।अन्यायोपार्जितं वित्तं दस वर्षाणि तिष्ठति।

प्राप्ते चैकादशेवर्षे समूलं तद् विनश्यति।।...आचार्य चाणक्य अपने इस श्लोतक में कहते हैं कि ऐसे गलत तरीकोंसे कमाया गया पैसा बमुश्किल 10 साल तक ही रहता है, इसके बाद 11वें वर्ष से ही ऐसा पैसा धीरे-धीरे नष्ट होने लगता है, इसलिए व्यक्ति को कभी भी अनैतिक तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए क्योंकि उसे बुरे कर्मों का फल भी झेलना पड़ता है और कुछ समय बाद ऐसे धन नष्ट भी हो जाता है, फिर चाहे वजह कोई दुर्घटना, बीमारी, नुकसान या अन्य कारण हो। बेहतर होगा कि ईमानदारी से पैसा कमाएं और उसका एक हिस्सान दान में दें, इससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी और आप दिन-दूनी रात-चौगुनीतरक्की करेंगें।

साथियों बात अगर हम चाणक्य नीति की करें तो, उसके अनुसार पापकर्म द्वारा या किसी को कष्ट और क्लेश पहुंचाकर कमाया पैसा अभीशापित होकर मनुष्य का नाश कर देता है। इस धन के प्रभाव से सज्जन पुरुष भी पाप की और बढ़ने लगते हैं। इसलिए ऐसे पैसों से बचना चाहिए, वरना जल्दी ही कुल सहित उस इंसान का नाश हो जाता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि ऐसा धन दस साल से ज्यादा नहीं टिक पाता। उसके बाद दुगना खर्चा बीमारी या नुकसान होकर ऐसा पैसा चला जाता है।

साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार जैसे गलत स्त्रोतों से कमाए गए धन के परिणामों की करें तो हम इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में भ्रष्टाचारियों के अनेक दुखद नकारात्मक परिणामों के बारे में पढ़ते सुनते रहते हैं परंतु मेरा यह निजी और व्यक्तिगत रूप से अपने साथियों दोस्त अफसरों के अनुभव की जानकारी रेखांकित किया हूं कि जो भ्रष्टाचार करता है वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता उसके परिवार, बच्चे कुल में संकटों का पहाड़ किसी न किसी रूप में गिरता ही रहता है और सबसे बड़ी बात, कि मां लक्ष्मीत चंचल होती हैं, यदि गलत तरीकों से धन कमाया गया तो मां लक्ष्मीं नाराज होकर चली जाती हैं,अनैतिक तरीकों से चोरी, धोखे, अन्यांय, जुआ आदि के जरिए कमाया गया धन हमेशा साथ नहीं रहता है।

साथियो हमने देखे होंगे कि भ्रष्टाचारियों के पास धन अधिक समय तक नहीं रहता वह निकल जाता है सुबह नहीं तो शाम निकलता जरूर है जिसकी परिणति हम बड़े बड़े ऑफिसरों नेताओं ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड से करोड़ों रुपए के धन की बरामदगी के रूप में किससे मीडिया में देखते सुनते रहते हैं।

अशोक अग्रवाल

चलें जड़ों की ओर

प्राकृतिक संरक्षण एवं सामाजिक चेतना

भारत में जल प्रदूषण एक गम्भीर समस्या है, और 50% नदियां प्रदूषित मानी जाती हैं, जिससे पीने और सिंचाई के लिये पानी असुरक्षित हो गया है। इसके पीछे मुख्य कारण हैं, अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह, और कचरे का अनुचित निपटान। इसके चलते जलजनित बीमारियां, पर्यावरणीय क्षति और जल संकट जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत की कुल 10368 नदियों में से आधे से अधिक नदियां प्रदूषित हैं। प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, ब्रम्हपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा आदि प्रमुख नदियों में से हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तराखण्ड में गंगोत्री ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी तक कुल 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। गंगा नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के मैदानों वाले हिस्सों में पाया जाता है। कानपुर और वाराणसी के बीच औद्योगिक कचरा, सीवेज और शहरों का गंदा पानी सीधे नदी में गिरता है।

कानपुर के पास जाजमऊ- यहां पर इतरा अधिक प्रदूषण है कि जलीय जीवों के लिये जीना मुश्किल है।

बिहार और झारखंड के नीचे वाले हिस्सें कृषि रसायन और नगर का कचरा सीधे नदी में मिल रहा है।

पश्चिमी बंगाल का निचला भाग यहां पेस्टिसाइड और भारी धातुओं की मात्रा तुलनात्मक रूप से अत्यधिक पाई जाती है।

जल में जिंक, तांबा, सीसा, कैडमियम क्रोमियम धातुओं का पानी में होना स्वास्थ्य और जलीय जीवन के लिये खतरा होता है।

भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। भारत की सबसे साफ नदी उमंगोट नदी है, जो मेघालय राज्य में स्थित है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है इसका उद्गम उत्तराखण्ड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का केवल 2% जो 52 किलोमीटर होने के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नदी के कुल प्रदूषण में 79% का योगदान देता है, जिससे यमुना का यह भाग सबसे प्रदूषित है। दिल्ली में यमुना में प्रदूषण का मुख्य स्रोत घरेलू अपशिष्ट हैं, जो कुल प्रदूषण का 85% है। अन्य में औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह, ठोस अपशिष्ट और सूक्ष्म प्लास्टिक शामिल हैं।

एक अध्ययन में यह भी पता चला है कि शहर मे 792 मिलियन गैलन (एमजीडी) सीवेज उत्पन्न होता है। इसमें से केवल 618 एमजीडी का ही ट्रीटमेन्ट हो पाता है, ट्रीटमेन्ट किये गये इस पानी का लगभग 30 प्रतिशत अभी भी निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहता है। पानी में मुख्य विषैले तत्वों में फ्लोराइड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड कई गुना प्राप्त हुआ है। यदि कुछ विशेषज्ञों की माने तो लंबे समय तक अत्यधिक आयरन वाले पानी से सींची गई सब्जियां खाने से उनमें आयरन की मात्रा जमा हो सकती है। इससे मानव शरीर में भी आयरन की अधिकता हो सकती है जिससे लिवर और आंतो पर बुरा असर पड़ता है। इसके कारण पाचन संबंधी समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त और पेट दर्द हो सकता है एवं इससे बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है।

भारत में वायु प्रदूषण : कारण एवं निदान

भारत में इस समय सबसे अधिक वायु प्रदूषण औद्योगिक गतिविधियों से हो रहा है, जो लगभग 52% प्रदूषण का कारण है।

2025 में भारत के सबसे प्रदूषित शहर

1 हापुड़ उत्तर प्रदेश 416 पीएम 2.5
2 नोयडा उत्तर प्रदेश 397 पीएम 10, पीएम 2.5
3 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 396 पीएम 10, पीएम 2.5
4 दिल्ली दिल्ली 382 पीएम 2.5
5 ग्रेटर नोयड़ा उत्तर प्रदेश 382 पीएम 2.5
6 चरखी दादरी हरियाणा 366 पीएम 2.5
7 बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश 356 पीएम 2.5
8 मैरठ उत्तर प्रदेश 350 पीएम 10, पीएम 2.5
9 मानेसर हरियाणा 342 पीएम 2.5
10 बाघपत उत्तर प्रदेश 330 पीएम 2.5

इसके बाद वाहनों से 26%, फसल जलाने से 17% और बाकी अन्य स्त्रोतों से 5% प्रदूषण होता है।

वर्ष 2024 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 21 लाख मौतें हुई, जो कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट में बताया गया है। होने वाली मौतों में लगभत 36% मौतें फेफड़ों के कैंसर से, 34% स्ट्रोक से और 27% हृदय संबंधी बीमारियों से होती हैं। बाकी मौंते अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण होती है।

भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय (स्ल्ह्रश्वस्न × ष्ट्ट) को कुल रूपये 3,330.37 करोड़ का बजट दिया जिसमें रूपये 858.5 करोड़ विशेष रूप से प्रदूषण

नियन्त्रण के लिये आरक्षित थे। संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, रूपये 858.5 करोड़ में से केवल रूपये 7.22 करोड़ ही व्यय हुये, यानी कुल स्वीकृत राशि का 1% से भी कम उपयोग हुआ। खर्च न होने के बारे में बताया गया कि योजना की आगे की अवधि के लिये स्वीकृति का अभाव था, इसलिये राशि व्यय न ही हो पाई।

सुरक्षित सीमा (0 से 50) के बहुत ऊपर है। ये कण श्वसन तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं जैसे अस्थमा, हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ाना। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है।

1. औद्योगिक प्रदूषण : बड़े शहरों में कारखानों और औद्योगिक इकाइयां हवा में प्रदूषण छोड़ती हैं, जिसके कारण कड़े नियमों के अभाव में अनियन्त्रित उत्सर्जन होता है।

2. वाहनों से होने वाला प्रदूषणः बड़े शहरों में भारी यातायात के कारण वायु

प्रदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेटर मैटर का उत्सर्जन होता है।

3. निर्माण गतिविधियां शहरों में चल रही निर्माण परियोजनाओं से धूल और

कण उत्पन्न होते हैं, यह शुष्क मौसम में विशेष रूप से समस्या जनक होता है, जब धूल आसानी से हवा में फैल सकती है।

4. फसल जलाना :- पराली जलाने जैसी प्रथाएं वायु प्रदूषण में मौसमी वृद्धि का कारण बनती हैं। आसपास की कृषि गतिविधियां वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

भारत में सबसे अधिक वायु प्रदूषण कोयला, बायोमास और धूल के द्वारा होता है। कोयले का सबसे अधिक उपयोग बिजली बनाने तथा उद्योगों में किया जाता है तथा दूसरे स्त्रोतो के रूप में बायोमास का उपयोग किया जाता है, वर्ष 2024 में भारत में भारत में विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 792.958 मीट्रिक टन थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 755.029 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की गई थी, जो 5.02% की वृद्धि है।

धूल के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ा है, जंगलों की कटाई, स्टेट हाईवे के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने पर लगभग 50 वर्ष पुराने पेड़ काटे गये जिससे एक तरफ लाभ तो हुआ परन्तु पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे झारखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक लगभग 1,05,753 पेड़ काटे गये। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में कितना वायु प्रदूषण होता है, औसतन हर मिनट देश में 2400 पेड़ काटे जाते हैं। 2024 में सम्पूर्ण भारत में 18 हजार हेक्टेयर जंगल कम हुआ जिसमें कटाई के साथ-साथ वनों में आग का भी योगदान रहा है।

ग्लोबल फारेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2001-2024 के बीच देशभर में 2.31 मिलियन हैक्टेयर वृक्ष आवरण नष्ट हुआ है। मई 2025 में मुझे माताजी के स्वर्गवासी होने पर अस्थी कलश लेकर गंगाजी में कछला (गंगा जी का घाट) जाने का मौका मिला, मथुरा बरेली 530 क्राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य चल रहा था जिसकी लम्बाई 265 किलोमीटर है, पूर्व में यह रोड स्टेट हाइवे था जिसको चौड़ा किया गया, पूर्व में मैंने देखा था कि पूरे रोड पर शीशम, जामुन, नीम आदि वृक्षों का सघन वृक्षारोपण था। पूरे वृक्ष अत्यधिक पुराने एवं विशाल थे, परन्तु आज पूरे रोड़ पर एक भी पेड़ नहीं हैं, इसके निर्माण में लगभग 5,660 पेड़ों की कटाई की गई।

पेड़ों की कटाई और आग लगने की घटनाओं से देश की 5,57,665 वर्ग किलोमीटर जमीन बंजर हो चुकी है, जो कुल क्षेत्रफल का 16.96% है।

महानिदेशक भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद् के अनुसार 50 साल में एक पेड़ 52 लाख 400 रूपये से अधिक की सुविधा प्रदान कर सकता है। इनमें 11 लाख 97 हजार 500 रूपये की ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। यही ऑक्सीजन प्राणवायु का काम करती है। इतने सालों में यही एक पेड़ 23 लाख 68 हजार 400 रूपये का वायु प्रदूषण नियन्त्रित करता है, जबकि 19 लाख 97 हजार 500 रूपये मूल्य की भूक्षरण नियन्त्रण व उर्वरता बढ़ाने में सहयोग करता है। बारिश के पानी को रोकने, कटाव रोकने, जल को रिसाइकिल करने में रूप में 4 लाख 37 हजार रूपये का योगदान देता है।

इस तरह एक पेड़ हमें 50 साल में 52 लाख 400 रूपये से अधिक का फायदा पहुंचाता है।

पीएल ओएस ग्लोलब पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में समय से पहले जन्म और कम बजन वाले बच्चों के जन्म का सीधा संबंध वायु प्रदूषण से है।

एक अध्ययन में भारत, थाइलैण्ड, आयरलैण्ड और यूके के संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.) के आँकड़ों और उपग्रह डेटा के आधार पर तैयार किया गया था। इस डेटासेट में 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चे शामिल थे जिसमें 52% लड़कियां और 48% लड़के शामिल थे।

अध्ययन परिणामों के अनुसार गर्भावस्था के दौरान सूक्ष्मकण पदार्थ (पीएम 2.5) के सम्पर्क में आने से इनके प्रतिकूल परिणामों की सम्भावना काफी बढ़ जाती है, गौरतलब है कि पी एम 2.5 में 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले वायु जनित कण होते हैं।

अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, पी.एम. 2.5 के उच्च स्तर के सम्पर्क में आने वाली गर्भवती महिलाओं में समय से पहले प्रसव का खतरा 70% बढ़ जाता है, वायु प्रदूषण के अधिक सम्पर्क में आने से जन्म के समय कम वजन का खतरा 40 % बढ़ जाता है तथा पीएम 2.5 के स्तर में 10 ग्राम/घन मीटर की वृद्धि से समय से पहले जन्मदर में 12% की वृद्धि होती है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 2019-21 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में 13% बच्चे समय से पहले पैदा हुये और 17% का जन्म के समय वजन कम था, इसका एक प्रमुख कारण गर्भावस्था के दौरान प्रदूषित हवा के सम्पर्क में आना है। निदानः- वायु प्रदूषण को कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:-

1. उद्योगों में साफ-सुथरी तकनीकों का उपयोग।

2. वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।

3. सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना

4. कचरे का सही प्रबन्धन।

5. पेड़ों की अधिक से अधिक संख्या बढ़ाना।

6. सड़कों के किराने वृक्षारोपण का कार्य कराने के लिये रोड के किनारे जिन किसानों के खेत हैं उन्हें ही जमीन लीज पर दी जा सकती है, जिसमें 40% पीपल, नीम, बरगद आदि के पेड़ एवं 60% में किसान अच्छी किस्म के फलदार वृक्ष लगा सकता है जिससे किसान को अच्छी आय होगी। ऐसा देखा जाता है कि शासकीय जमीन पर लगाये गये पेड़ किसानों द्वारा ही काट दिए जाते हैं क्योंकि उनकी जमीन में वृक्षों की छाया से फसल प्रभावित होती है।

7. आज से कुछ समय पूर्व खेतों में फलदार वृक्षों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी परन्तु फसल को हानि की वजह से किसानों ने पेड़ों को काट डाला, किसानों को प्रोत्साहित किया जाये और अच्छे किस्म के फलदार वृक्ष उपलब्ध कराये जायें जिनका किसान द्वारा मेड़ों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए, जिससे किसान को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी एवं पर्यावरण संरक्षण के यज्ञ में भी योगदान मिलेगा।

8. एक मेढ़ 5 पेड़ का नारा किसानों को देना होगा।

9. जगह-जगह पर पुराने तालाब, कुएं, बाबड़ी आदि जल स्त्रोतों को बन्द कर दिया है उन सबको पुर्नजीवित करना होगा।

10. लोगों में जागरूकता फैलाना।

दुनिया में 99% लोग दूषित हवा में सांस ले रहे हैं, इससे दुनिया भर के लोगों की औसत आयु 2.2 साल घट गई है। शिकागो यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में जारी किये गये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार यदि भारत के लोगों को शुद्ध हवा मिले तो उनकी औसत उम्र 5 साल तक बढ़ सकती है, इस बात से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण को कम करना कितना आवश्यक है।

प्राकृतिक संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। जब तक समाज जागरूक और सहभागी नहीं बनेगा, तब तक संरक्षण के प्रयास सीमित रहेंगे। अतः प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, संसाधनों का संयमित उपयोग करें और दूसरों को भी जागरूक करें।

प्राकृतिक संरक्षण और सामाजिक चेतना का समन्वय ही सतत, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की कुन्जी है।

डॉ. यशपाल सिंह

(लेखक- सलाहकार जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल एवं (राष्ट्रपति पुरस्कार, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार एवं अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हैं)

पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी ,जला रही संस्कारों की होली

व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। संस्कारों की प्रथम पाठशाला मां होती है। कहते हैं कुम्हार मिट्टी को जैसा आकार देता है वैसा ही घड़ा बन जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वे संस्कारों की सीढ़ी पर चढ़कर ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल हुए हैं।संस्कारों से ही संस्कृति की रक्षा होती है। वर्तमान में मां-बाप बच्चे को अच्छे संस्कार देने को जागरुक नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण एवं वर्तमान भौतिक चकाचौंध में वहकर युवा पीढ़ी संस्कार को भूलकर पतन की ओर अग्रसर हो रही है।

युवा पीढ़ी को ही पतन के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते,कुसंस्कार के लिए हम भी दोषी हैं। बालक को गर्भावस्था में मां से संस्कार मिलते हैं। महान योद्धा अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश की शिक्षा अपनी माता से गर्भ में मिली थी। संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। जिसका चरित्र उज्जवल होता है उसकी पूजा होती है। संस्कारों को वृति कहते हैं, वृति से ही हमारी प्रवृत्ति बनती है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले चलकर हम देखें तो बालक को जन्म के साथ ही माता-पिता अच्छे संस्कार प्रदान कर सफल जीवन की ओर बढ़ाते थे। बालक बालिकाओं की सह शिक्षा का निषेध था। बालक बालिकाओं की दैनिक गतिविधियों पर परिवार की पैनी नजर रहती थी। वर्तमान में युवा पीढ़ी में जो संस्कारविहीनता आई है।उनसे आप भली-भांति परिचित हैं। प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, प्रत्येक शनिवार को क्लवों में युवक युवतियों की नाईट आउट पार्टियां,गर्भपात, भ्रूण हत्या, विवाह पूर्व फिल्मांकन, मोबाइल की गंदी आदत से आत्महत्या करना, हुक्का पब क्लवों में नशाखोरी, बिना विवाह किये लिव इन रिलेशनशिप में रहना,माता-पिता को वृद्धा आश्रम में रहने की मजबूरी, अनैतिक तरीके से धन उपार्जन करना। आदि अनेक गलत आदतें युवा पीढ़ी में बढ़ रही है।

वर्तमान में युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर आसीन हो रहे है। विदेश जाकर नौकरी करने की स्पर्धा चल रही है। मेरा मत है कि हम नौकरी या व्यवसाय करें, मगर हमें अपने मूलभूत संस्कारों का पालन करते हुए कार्य करना चाहिए।आधुनिक संचार क्रांति मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम,ट्यूटर के जितने लाभ है उससे ज्यादा इन सुविधाओं का दुरुपयोग हो रहा है। युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने में इनका पूर्ण योगदान है। प्रातः काल उठकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में दर्शन करने जाना,पानी छानकर पीना, रात्री भोजन नहीं करना आदि मूलभूत आचरण अब परिवार के वरिष्ठ जनों के जिम्मे रह गये हैं।परिवार में कुलाचार का पालन होता था, हम कुलाचार को भूल गए हैं। कुलाचार के पालन से दुराचार से बचते थे, मुनिराज, साधु संत निरंतर युवा पीढ़ी को सद् मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रसंत समाधिस्थ मुनि तरुण सागर जी महाराज ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें तीन संकल्प दिलाये थे। 1, जीवन में निराश होकर कभी आत्महत्या नहीं करूंगा। 2. वृद्ध माता-पिता का सम्मान करुंगा, अपने परिवार के साथ रखूंगा। 3. देश प्रेम की भावना से कमी नहीं करूंगा।

सराकोद्धारक समाधिस्थ आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज ने शाहदरा दिल्ली में विगत वर्षों विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए युवा पीढ़ी को आह्वान किया था कि माता-पिता का ही बेटा है तो वह संकल्प ले कि माता-पिता को छोड़कर विदेश नौकरी के लिए नहीं जाएगा। दो बेटे हैं तो एक नौकरी करेगा, दूसरा अपना पारिवारिक व्यवसाय करेगा। आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज के परम प्रिय शिष्य तीर्थ उद्धारक संस्कार प्रणेता निर्यातक श्रमण मुनि सुधासागर जी महाराज का स्पष्ट कहना है युवा पीढ़ी को संस्कार विहीन एवं पथभ्रष्ट बनाने माता पिता ही दोषी हैं।माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को शैशव अवस्था में ही मां उन्हें मोबाइल देकर मोबाइल में गेम देखने की आदत डाल देती है।

और बच्चे युवावस्था में पथ भ्रष्ट हो जाते हैं।देश में युवाओं में संस्कारों की अलख जगा रहे सुप्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मुनि चंद्रप्रभ जी महाराज ने मंगल प्रवचन करते हुए कहा जिस परिवार में माता-पिता का सम्मान नहीं होता है परिवार मरघट के समान है। दिगंबर जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने प्रवचन करते हुए कहा आप कितना भी पैसा कमा लें आपका चरित्र उज्जवल नहीं है तो सब बेकार है। चरित्र का निर्माण तभी होता है जब संस्कारों की शिक्षा दी जाएगी। मुनिराज ने माताओं को प्रेरणा दी कि आप जितना ध्यान अपने बेटे की शिक्षा पर देती हैं उतना ही ध्यान उसे संस्कार देकर चरित्रवान बनाने दें। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य ऐलक सिद्धांत सागर जी महाराज देश भर में संस्कार मेला लगाते हैं।

साधु संतों से हमें संस्कारवान बनकर अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है अपने उपदेशों को जीवन में उतारने वालों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। जैन मुनियों साध्वियों का प्रवास होता है वह लड़कियों को यह संकल्प दिलाते हैं कि मंदिर जी एवं प्रवचन सभा में आधुनिक वस्त्र जींस टॉप पहनकर नहीं आना है।

मगर बिडंवना यह है कि जब तक संत विराजमान रहते हैं, उनके संकल्प का पालन होता है उनके विहार करते ही आधुनिक वस्त्र पहनना चालू हो जाता है। प्राचीन काल में महिलाओं से कुल की मर्यादा का पालन कराया जाता था। लड़कियों व महिलाओं का पहनावा ऐसा होना चाहिए जिसे पहनकर संस्कृति की रक्षा हो।संस्कार विहीन युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट होने से रोकने समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए युवा पीढ़ी संस्कार विहीन होगी तो समाज व देश की संस्कृति की रक्षा कैसे होगी।

विजय कुमार जैन

(लेखक स्थायी अधिमान्य स्वतंत्र पत्रकार एवं भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं।)

सरकार को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा

डॉ योगेन्द्र

बाजार में लुटेरे व्यापारियों ने हल्ला किया कि प्याज की कीमत सौ रुपए किलो हो गई है। जबकि प्याज की वास्तविक कीमत पच्चीस रुपए किलो थी। ग्राहक परेशान। वे सरकार के पास पहुंचे। हल्ला गुल्ला किया। सरकार ने आश्वासन दिया कि लुटेरे व्यापारियों पर कार्रवाई की जायेगी। सरकार ने रात के अंधेरे में लुटेरे व्यापारियों से समझौता किया। दोनों में लेन देन हुई। प्याज की कीमत पचास रुपए किलो कर दी गई। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। ग्राहक के सामने अपनी अकड़ दिखाई और कहा कि देखे, मैंने लुटेरे व्यापारियों को सीधा कर दिया। ग्राहक सब-कुछ समझ रहा है, लेकिन मसोसकर रह जाता है। पच्चीस रुपए का प्याज पचास रुपए में मिल रहा है। उसकी जेब पतली हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे? सरकार और अमेरिका की डील कुछ ऐसी ही है। पहले ट्रंप भारत को धमकाता है कि कच्चा तेल हमसे खरीदो, वरना तुम्हारे सामान पर पच्चीस प्रतिशत टैरिफ लगायेंगे और नहीं माने तो तुम्हें दंडित करेंगे और टैरिफ पचास प्रतिशत करेंगे। एक अरब चालीस करोड़ का प्रधानमंत्री चुप, वाणिज्य मंत्री चुप और विदेश मंत्री मुंह चुराते रहे। छप्पन इंच का कलेजा कबूतर का हो गया। उस पर खासमखास मित्र और उनके फिनांसर अडानी पर केस और ऊपर से एपस्टीन फाइल। अचानक एक दिन अमेरिका ने खबर दी कि भारत से डील हो गई। अब हमारे सामान पर भारतीय बाजार में बिना टैरिफ के पहुंचेगा और भारत के सामान पर अट्ठारह प्रतिशत टैरिफ लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गये चुनावी मंच पर और गरजने लगे - झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महज 2.93 प्रतिशत टैरिफ पर जो डील किया था, वह अट्ठारह प्रतिशत हो गया। गजब , बेशर्म है सरकार और बेशर्म हैं उनके समर्थक। पंगुपना खानदानी होता है। अंग्रेजों से माफी मांगते मांगते, अब बदतमीज ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इस डील से सर्वाधिक हानि किसानों को होगी। अमेरिका अपने किसानों को अभूतपूर्व सब्सिडी देता है और भारतीय किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है।अब भारतीय बाजार में अमेरिका के ताजे फल, प्रोसेस्ड फूड, बादाम, अखरोट, सोया आयल धड़ल्ले से बिकेगा। भारत के वाणिज्य मंत्री की हालत देखिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तब उनका जवाब था कि विदेश मंत्री ज़वाब देंगे। जब यही सवाल विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया, तो उनका जवाब था कि इस प्रश्न का उत्तर वाणिज्य मंत्री देंगे। ये लोग देश? चला रहे हैं ! अमेरिका छाती ठोक कर कह रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत की नीतियों की घोषणा अमेरिका कर रहा है। क्या भारत अमेरिका का बंधक नहीं हो गया है? एक स्वाभिमानी देश? या समाज या व्यक्ति जान दे देगा, लेकिन स्वाभिमान नहीं बेचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश? को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। पाकिस्तान - भारत के बीच हुए युद्ध को बंद करवाने से लेकर रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने की घोषणा ट्रंप कर रहा है। मजा यह है कि जो डील राष्ट्रीय शर्म का विषय है, उसे राष्ट्रीय गौरव की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। दरअसल आज भारत की अपनी कोई विदेश नीति नीति नहीं है। घर में कोसने के लिए नेहरू हैं, गलियाने के लिए कांग्रेस है और राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए हिन्दू - मुसलमान है। घर से बाहर मौज मस्ती है, गिड़गिड़ाना है। भारत सरकार की इतनी लुंज-पुंज हालत देश को शर्मसार कर रही है। मनमोहन सिंह की छाती तो छप्पन इंच की नहीं थी, लेकिन उनकी छाती में स्वाभिमान और देशभक्ति की भावनाएं बहती थीं। यहां तो सुनार की भाथी की तरह कलेजा है, भांय - भांय करता है।

स्क्रीन की गिरफ्त में बचपन : मोबाइल, मानसिक सेहत और हमारी ज़िम्मेदारी, मगर सरकार गंभीर नहीं

गाजियाबाद की घटना ने एक बार फिर समाज को झकझोर दिया है। बच्चों और किशोरों की दुनिया में मोबाइल कैसे चुपचाप केंद्र बनता जा रहा है, यह सवाल किसी एक परिवार या एक शहर तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल स्क्रीन ने सीखने, मनोरंजन और संवाद के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन जब वही स्क्रीन वास्तविक रिश्तों, भावनात्मक सहारे और जीवन की जटिलताओं को समझने की क्षमता पर हावी हो जाए, तब जोखिम बढ़ जाता है। यह लेख किसी घटना का सनसनीखेज़ विवरण नहीं, बल्कि उस व्यापक परिदृश्य पर विचार है जिसमें बच्चे, परिवार, सरकार और समाज सबकी साझा ज़िम्मेदारी बनती है।

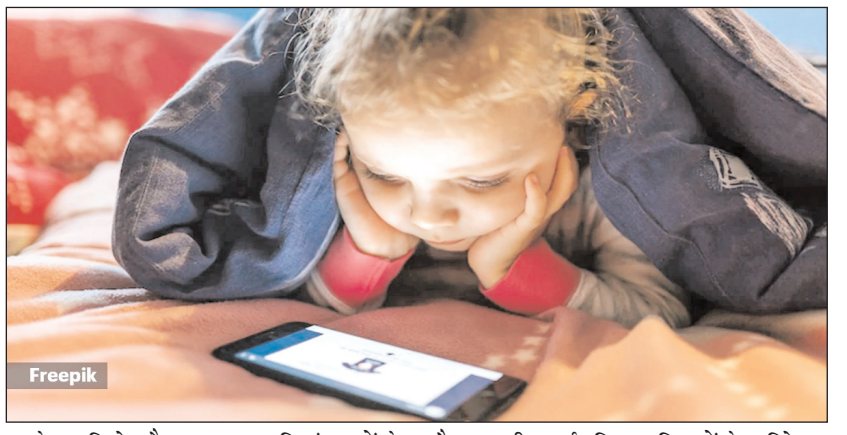

आज का बच्चा बहुत जल्दी स्क्रीन से परिचित हो जाता है। छोटे हाथों में स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी रिमोट अब असामान्य नहीं हैं। वैश्विक और भारतीय अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि लंबे समय तक स्क्रीन के संपर्क में रहने से नींद, ध्यान, भावनात्मक संतुलन और सामाजिक व्यवहार प्रभावित होते हैं। जब स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तो खेल, पढ़ाई, परिवार के साथ बातचीत और खुले वातावरण में बिताया समय घटता है। यह कमी धीरे-धीरे भावनात्मक अकेलेपन और चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है, जिसे कई बार बच्चे खुद शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते।

मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर विशेष चिंता का विषय है। शोध बताते हैं कि बहुत अधिक स्क्रीन टाइम वाले बच्चों में उदासी, निराशा और सामाजिक अलगाव के लक्षण अपेक्षाकृत अधिक दिखते हैं। नींद की कमी इस प्रभाव को और गहरा करती है। देर रात तक स्क्रीन पर रहने से शरीर की प्राकृतिक घड़ी बिगड़ती है, जिससे अगले दिन थकान और भावनात्मक असंतुलन बढ़ता है। यह कोई सीधी रेखा नहीं कि हर स्क्रीन देखने वाला बच्चा संकट में होगा, लेकिन जोखिम का स्तर अवश्य बढ़ता है, खासकर तब जब स्क्रीन का उपयोग बिना मार्गदर्शन और संवाद के हो।

डिजिटल संस्कृति के साथ वैश्विक पॉप ट्रेंड्स का आकर्षण भी बढ़ा है। कोरियाई ड्रामा, संगीत, भाषा और भोजन के प्रति भारत में रुचि तेज़ी से बढ़ी है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान अपने आप में सकारात्मक हो सकता है, लेकिन जब आभासी दुनिया वास्तविक जीवन की अपेक्षाओं का स्थान लेने लगे, तब भ्रम पैदा होता है। आदर्श जीवन, परफेक्ट रिश्ते और चमकदार छवियां बच्चों के मन में तुलना और असंतोष को जन्म दे सकती हैं। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि जिन देशों की पॉप संस्कृति लोकप्रिय है, वहां भी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां मौजूद हैं। खुशी के सूचकांक और सामाजिक भरोसे में गिरावट जैसे तथ्य बताते हैं कि चमकदार परदे के पीछे की सच्चाई कहीं अधिक जटिल है।

ऐसे में सवाल उठता है कि समाधान क्या है। सबसे पहले, सरकार की भूमिका पर बात ज़रूरी है। डिजिटल इंडिया के दौर में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा और मानसिक सेहत को नीति की प्राथमिकता बनाना होगा। स्कूल पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी कौशल तक सीमित न रखकर स्क्रीन के स्वस्थ उपयोग, ऑनलाइन व्यवहार, भावनात्मक स्व-नियंत्रण और मदद मांगने की संस्कृति तक विस्तारित करना चाहिए। सरकारी स्कूलों से लेकर निजी संस्थानों तक, काउंसलिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ानी होगी, ताकि बच्चे बिना डर अपनी बात कह सकें। बाल-अनुकूल हेल्पलाइन, समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण, यह सब मिलकर एक सुरक्षा-जाल बना सकते हैं।

नियमन का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए कंटेंट रेटिंग, विज्ञापन नियंत्रण और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आयु-उपयुक्त सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना होगा। टेक कंपनियों के साथ साझेदारी कर 'डिफ़ॉल्ट' स्क्रीन-लिमिट, ब्रेक रिमाइंडर और रात के समय नोटिफ़िकेशन नियंत्रण जैसे फीचर्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही, सार्वजनिक अभियानों के ज़रिये यह संदेश पहुंचाना होगा कि स्क्रीन का संतुलित उपयोग ही लाभकारी है, असीमित नहीं।

पर सरकार अकेले यह लड़ाई नहीं जीत सकती। घर वह पहली जगह है जहां बच्चे दुनिया को समझते हैं। अभिभावकों की भूमिका निर्णायक है। मोबाइल को पूरी तरह प्रतिबंधित करना व्यावहारिक नहीं, लेकिन स्पष्ट सीमाएं तय करना आवश्यक है। उम्र के अनुसार स्क्रीन टाइम, सोने से पहले स्क्रीन बंद करने की आदत, और सप्ताह में कुछ घंटे 'डिवाइस-फ्री' समय तय करना छोटे लेकिन प्रभावी कदम हैं। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है संवाद। बच्चों से केवल नियम न कहें, उनके अनुभव सुनें। वे क्या देख रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं, उससे उन्हें कैसा महसूस होता है।इन सवालों पर खुली बातचीत विश्वास बनाती है।

अभिभावक स्वयं उदाहरण बनें तो असर दोगुना होता है। यदि घर में बड़े लोग भी हर खाली पल स्क्रीन पर बिताते हैं, तो बच्चों से संयम की उम्मीद करना कठिन है। परिवार के साथ भोजन, खेल, किताब पढ़ना या बाहर टहलना, ये सब साधारण लगते हैं लेकिन भावनात्मक सुरक्षा का आधार बनते हैं। बच्चों की रुचियों को ऑफ़लाइन गतिविधियों से जोड़ना, जैसे खेल, संगीत, कला या सामाजिक सेवा, उन्हें संतुलन सिखाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

स्कूलों की जिम्मेदारी भी कम नहीं। शिक्षा केवल अंकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भावनात्मक शिक्षा, सहानुभूति, टीमवर्क और समस्या-समाधान जैसे कौशलों को कक्षा का हिस्सा बनाना होगा।

जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधीजी के पदचिन्हों पर चलना शुरू किया

मार्टिन लूथर किंग जूनियर

15 जनवरी,1929 -- 04 अप्रैल, 1968

भारत में तीर्थ यात्रा -10 फरवरी से 10 मार्च, 1959

मेरा एक सपना है भाषण के लिए प्रसिद्ध, नागरिक अधिकारों का पक्षधर, बैपटिस्ट पादरी, अहिंसा में विश्वास रखने वाला तीस वर्ष का एक अमरीकी नागरिक अपनी पत्नी के साथ सत्य, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के देश में उन स्थानों, कार्यों को देखने के लिए पधारे, जो गांधीजी से संबंधित रहे। अपनी इस यात्रा को उस महापुरुष ने तीर्थ यात्रा का नाम दिया। केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि द्वारा निमंत्रित यह व्यक्ति और कोई नहीं स्वयं रंगभेद, असमानता के विरुद्ध अमेरिका में अहिंसक आंदोलन चलाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जो अपनी पत्नी श्रीमती कोरेटा स्कॉट किंग के साथ भारत आए थे। 10 फरवरी से 10 मार्च, 1959 तक यह यात्रा हुई। दिल्ली से शुरू कर बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए फिर दिल्ली।

श्रीमती सुचेता कृपलानी, उपाध्यक्ष एवं जी रामचंद्रन, मंत्री, गांधी स्मारक निधि ने हवाई अड्डा पर मेहमानों का स्वागत किया।

तीर्थ यात्रा की समाप्ति पर बहुत ही भावनात्मक ढंग से विदाई से पूर्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिल्ली में यह संदेश दिया, जो आज भी बेहद प्रासंगिक है।

भारत की हमारी बहुत ही छोटी तीर्थयात्रा दुख की बात है कि खत्म हो गई है।

मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे, मेरी पत्नी और डॉ. रेडिक के लिए अपने दरवाजे और दिल खोले। सरकार के अंदर और बाहर के नेताओं, संगठनों --- खासकर गांधी स्मारक निधि और क्वैकर सेंटर --- और कई घरों और परिवारों ने हमारे छोटे से प्रवास को सुखद और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें की है।

हमने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा है। हम इतने नासमझ नहीं हैं कि यह मान लें कि हम भारत को जानते हैं --- यह एक विशाल उपमहाद्वीप है, जिसमें इसके सभी लोग, समस्याएँ, विरोधाभास और उपलब्धियाँ हैं। हालाँकि, क्योंकि हमसे हमारे विचारों के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम एक या दो सामान्य बातें कहना चाहेंगेः

सबसे पहले, हमें लगता है कि गांधी की भावना आज कुछ लोगों के विश्वास से कहीं ज़्यादा मजबूत है। न केवल उनके साथियों और सहयोगियों का सीधा और अप्रत्यक्ष प्रभाव है, बल्कि महात्मा के पत्रों और अन्य लेखों, तस्वीरों, स्मारकों, गांधी स्मारक निधि के काम और संत विनोबा भावे के नेतृत्व वाले आंदोलन को संरक्षित करने के लिए संगठित प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि जिनसे गांधीजी भारत के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसे रहेंगे।

इसके अलावा, कई सरकारी अधिकारी जो गांधी का अक्षरशः पालन नहीं करते, वे भी उनकी भावना को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लागू करते हैं।

दूसरा, मैं भारत के लोगों और सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ। विश्व शांति का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे एक सुझाव देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो विनोबाजी के साथ हमारी बातचीत के दौरान मेरे मन में आया।

दुनिया के शांतिप्रिय लोग अभी तक मेरे अपने देश, अमेरिका और सोवियत रूस को डर खत्म करने और खुद को निशस्त्र करने के लिए मनाने में सफल नहीं हुए हैं। दुर्भाग्य से, अभी तक अमेरिका और सोवियत संघ ने ऐसा करने के लिए विश्वास और नैतिक साहस नहीं दिखाया है। विनोबाजी ने कहा है कि भारत या कोई भी अन्य राष्ट्र जिसके पास विश्वास और नैतिक साहस है, वह कल ही, यहाँ तक कि एकतरफा भी, खुद को निशस्त्र कर सकता है।

हो सकता है कि जिस तरह भारत को नेतृत्व करना पड़ा और दुनिया को दिखाना पड़ा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता अहिंसक तरीके से हासिल की जा सकती है, उसी तरह भारत को नेतृत्व करना पड़े और सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण का आह्वान करना पड़े और अगर कोई अन्य राष्ट्र तुरंत उसके साथ शामिल नहीं होता है, तो भारत को एकतरफा रूप से खुद को निरस्त्रीकरण के लिए घोषित कर देना चाहिए।

साहस का ऐसा कार्य महात्मा की भावना का एक बड़ा प्रदर्शन होगा और यह बाकी दुनिया को भी ऐसा करने के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन होगा। इसके अलावा, जो भी देश ऐसा साहसी कदम उठाएगा, वह अपने आप ही दुनिया के लोगों का समर्थन हासिल कर लेगा, जिससे कोई भी हमलावर इंसानियत के गुस्से को मोल लेने का जोखिम उठाने से हतोत्साहित होगा।

यह संदेश आज भी देश और दुनिया के लिए बहुत ही प्रासंगिक एवं जरुरी है। इस संदेश में आज की समस्याओं, कठिनाइयों, हिंसा, शस्त्रों की होड़ में डूबी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता, राहत नजर आती है।

इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात अनेक प्रमुख लोगों से हुई। जिनमें सर्वोदय नेता संत बाबा विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद , उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजाजी राजगोपालचारी, दादा जे बी कृपलानी, डॉ जाकिर हुसैन, काका कालेलकर, यू एन ढेबर, मोरारजी देसाई, राजकुमारी अमृत कौर, डॉ सुशीला नैयर, प्यारे लाल नैयर, डॉ आर आर दिवाकर, जी रामचंद्रन, चीनी चिंतक प्रो तान युन शान, निर्मल कुमार बोस, डॉ सौन्द्रम रामचंद्रन, नंबूदरी पाद, शांति लाल शाह, पूर्व राजदूत जी एल मेहता आदि शामिल रहे।

दिल्ली में प्रैस कांफ्रेंस, राजघाट पर प्रार्थना, श्रद्धा-सुमन, मुगल गार्डन को देखना, क्वेकर केन्द्र एवं विभिन्न विशिष्ट लोगों से मुलाकात, स्वागत-सत्कार में भोज, चर्चा, बातचीत के साथ-साथ सप्रू हाउस में जनसभा, सर्वोदय कार्यकर्ताओं से बातचीत तथा रामजस कॉलेज में छात्रों के मध्य कार्यक्रम हुए।

पटना में राज्यपाल, मुख्यमंत्री से चम्पारण सत्याग्रह पर चर्चा। विश्वविद्यालय में छात्रों के मध्य कार्यक्रम। बौद्ध गया में बुद्ध विहार, बोधि वृक्ष का दर्शन, मुलाकात, विनोबा भावे द्वारा स्थापित समन्वय आश्रम में कार्यक्रम हुए। जयप्रकाश नारायण जी के सोखोदेवरा आश्रम में सादगी एवं ग्राम जीवन का अनुभव, विचार-विमर्श।

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती का सांस्कृतिक विरासत का दर्शन। शांति निकेतन में चीनी चिंतक से मुलाकात। कलकत्ता के प्रवास में मजदूर नेताओं से बातचीत का मौका मिला। ट्रेन के साथ-साथ ट्रक की भी यात्रा। विरोधाभास देखने को मिला। गांधी के साथ रहे निर्मल कुमार बोस से मुलाकात। कोरेटा स्कॉट किंग का आल इंडिया रेडियो स्टूडियो कार्यक्रम।

दक्षिण भारत की यात्रा ने और रुचि बढ़ाई। मद्रास में राजभवन में निवास। जनसभा एवं छात्रों की सभा। महाबलीपुरम, मदुरै, मीनाक्षी मंदिरों की विशालता देखी। मद्रास एवं गांधी ग्राम की यात्रा में खादी, ग्रामोद्योग, ग्राम दान से संपत्ति का बंटवारा, समतामूलक स्वावलंबी समाज की झलक दिखाई दी। ग्रामीण परिवेश, शांति सेना, अहिंसा का अनुशासन देखने का अवसर मिला। गांधी विचार पर चल रहे शैक्षणिक एवं आर्थिक प्रयोग देख कर प्रभावित हुए। राजाजी से हुई मुलाकात ने यात्रा को विशेष बना दिया। समुदायिक कार्यकर्मों का अवलोकन। हरिजन बस्ती में कार्यक्रम। केले के पत्ते पर जमीन पर बैठकर खाना खाया। पहली बार नारियल पानी एवं नारियल गिरी का स्वाद चखा। गांधी संग्रहालय मदुरै में कार्यक्रम।

गैर कांग्रेसी सरकार की राजधानी त्रिवेन्द्रम में मुख्यमंत्री ईएमएस नम्बुदरीपाद एवं राज्यपाल से मुलाकात। केरल में ऊंच शिक्षा दर। शिक्षित बेरोजगार एवं भोजन सामग्री के अभाव की बात सामने आई। त्रिवेन्द्रम में समुद्र स्नान एवं तैरने का आनंद लिया। कोरेटा स्कॉट किंग ने यहां कार्यक्रम में गाना प्रस्तुत किया। कोरेटा स्कॉट किंग गीत, संगीत में रुचि रखती थी। त्रिवेन्द्रम में बहुत बड़ी जन सभा का आयोजन हुआ।

भारत का एक छोर कन्याकुमारी प्रवास में सागर दर्शन का एकांत आनंद, गांधी मंडपम् , लोगों से मुलाकात। समुद्र के किनारे पत्थर की शिला पर ध्यान में बैठे। वहां पर पश्चिम में सूर्यास्त एवं पूर्व में चांद का अद्भुत नजारा देखा।

बंगलौर, मैसूर में उद्योगों, फैक्ट्रियों, औद्योगिक विकास की झलक देखी। पशु मेला देखा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित विभिन्न व्यक्तियों से मुलाकात, बातचीत। समयाभाव के कारण वृंदावन गार्डन का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। विश्व सांस्कृतिक संस्थान में जनसभा हुई।

बम्बई में मणि भवन का अनुभव शानदार रहा। गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष डॉ आर आर दिवाकर यहां साथ रहे। मणि भवन में गांधीजी के जीवन से जुड़ी सामग्री को देखने, गांधी विचार को समझने का अच्छा मौका मिला। गांधीजी के पत्र, चर्खा, बिस्तर, उनके उपयोग में लाई वस्तुओं को देखा। मणि भवन में भारत की आवाज नामक गांधी जी पर आधारित फिल्म देखी। ग्रीन होटल में नागरिकों की सभा में विस्तार से बताया। पूर्व राजदूत जी एल मेहता के यहां प्रमुख लोगों की सभा का आयोजन। अफ्रीकी छात्रों से मुलाकात, बातचीत। राज्यपाल, मुख्यमंत्री से मुलाकात। प्रैस कांफ्रेंस का आयोजन।

साबरमती नदी के किनारे स्थित साबरमती आश्रम, अहमदाबाद जहां से बापू ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी।इसका अपना ही अनुभव रहा। आश्रम प्रार्थना में शामिल हुए। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों से मुलाकात।

संत बाबा विनोबा भावे से मिलने तथा भूदान यात्रा में शामिल होने के लिए अजमेर, किशनगढ़, राजस्थान पहुंचे। जेपी साथ रहे। भूदान यात्रा में शामिल होना, साथ-साथ चलना, विनोबा भावे से बातचीत विशेष महत्वपूर्ण रहा।एक गांव में विनोबा भावे से बातचीत हुई। जो यादगार बन गई। भूदान यात्रा में बाबा के साथ चले।

मार्टिन लूथर किंग स्वास्थ्य के कारण शांति सेना के सम्मेलन में भाग नहीं ले सके। इसका दुःख रहा।

आगरा में ताज महल देखने गए। भारत में हिमालय, गांधी एवं ताज महल को बड़ा आश्चर्य मानते थे।

गांधी रचनात्मक कार्यों, स्थलों का दर्शन, गांधी जी से जुड़े व्यक्तियों से मुलाकात, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों से बातचीत, नागरिकों सभाओं में व्यक्त विचारों ने यात्रा को सार्थक, उपयोगी बनाया।

उस समय संत बाबा विनोबा भावे की भूदान यात्रा राजस्थान में चल रही थी। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण जी के साथ मार्टिन लूथर किंग विनोबा भावे जी से मिलने गए और भूदान यात्रा में शामिल हुए, पैदल भी चले। बाबा से उनकी मुलाकात एक यादगार अनुभव बना।

आज हिंसा, द्वेष, नफरत, अलगाव, झूठ, अविश्वास का बोलबाला बढ़ रहा है। शोषण-दोहन, लूट-खसोट, दबाव के दम पर अस्त्रों-शस्त्रों का धंधा जारी है। अमर्यादित पूंजी, पैसे के खेल में खुला अनैतिक, भ्रष्ट मनमानीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। विकास के नाम पर सुविधाओं से भरी दुनिया रचने का नाटक जारी है। सेवा, साधना, सादगी, सहजता-सरलता गायब है। श्रम को हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। विज्ञापन, प्रचार-प्रसार के नाम पर थोथी मगर चमक-दमक वाली दुनिया दिखाई जा रही है। मूल्य, मर्यादा खंडित हो रहे है। तथाकथित विकास के नाम पर दुनिया में गजब खेल चल रहा है। वह मानवता ही नहीं प्रकृति, सृष्टि के लिए भी बेहद घातक एवं विभत्स है। दुनिया को सर्वनाश की ओर ले जाया जा रहा है।

इसे क्या कहा जाए कि गांधी से प्रेरणा लेने वाले, अहिंसक आंदोलन में विश्वास रखने वाले, अहिंसा, करुणा, समता में विश्वास रखने वाले को भी अमेरिका में सहन नहीं किया गया। भारत में महात्मा गांधी को तीन गोलियां और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका में बम विस्फोट मिला।

महात्मा गांधी के देश भारत से विशेष आशा है कि वह दुनिया को अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकता है। गांधीजी ने अपने जीवन काल में इसे चरितार्थ करके दिखाया है। गांधी विचार दुनिया के लिए धरोहर है। हमें हिम्मत जुटाकर इसे आगे बढ़ाने में लगना होगा।

रमेश चंद शर्मा

हो सकता है कि जिस तरह भारत को नेतृत्व करना पड़ा और दुनिया को दिखाना पड़ा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता अहिंसक तरीके से हासिल की जा सकती है, उसी तरह भारत को नेतृत्व करना पड़े और सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण का आह्वान करना पड़े और अगर कोई अन्य राष्ट्र तुरंत उसके साथ शामिल नहीं होता है, तो भारत को एकतरफा रूप से खुद को निरस्त्रीकरण के लिए घोषित कर देना चाहिए। साहस का ऐसा कार्य महात्मा की भावना का एक बड़ा प्रदर्शन होगा और यह बाकी दुनिया को भी ऐसा करने के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन होगा। इसके अलावा, जो भी देश ऐसा साहसी कदम उठाएगा, वह अपने आप ही दुनिया के लोगों का समर्थन हासिल कर लेगा, जिससे कोई भी हमलावर इंसानियत के गुस्से को मोल लेने का जोखिम उठाने से हतोत्साहित होगा।

सीएम मोहन यादव बोले : नक्सली समस्या कैंसर के जैसी है

बालाघाट में पहली बार होगी... मध्यप्रदेश सरकार की बैठक

● बालाघाट।

एमपी के बालाघाट में नक्सली समस्या समाप्त होने के बाद पहली बार मोहन कैबिनेट की बैठक बालाघाट में होगी। इस बात की घोषणा सीएम डॉ. मोहन यादव ने की है। सीएम श्री यादव आज बालाघाट पहुंचे, यहां पर शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नक्सली गतिविधि पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

सीएम ने हॉक फोर्स के 60 जवानों को बैच लगाकर आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन दिया। जिन्होंने नक्सली मुठभेड़ में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। यह पदोन्नति उन जवानों को दी गई, जिन्होंने 14 जून 2025 को रूपझर थाना क्षेत्र के पचामादादर-कटेझिरिया पहाड़ी जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीएम ने जिले में 100 करोड़ 90 लाख रुपए के 27 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। सीएम ने पुलिस की विद्यांजलि कार्यक्रम, एकल केंद्र और 32 थानों के आईएसओ मिलने की शॉर्ट वीडियो फिल्म का शुभारंभ किया। बालाघाट में सीएम यादव ने नक्सली समस्या को कैंसर बताया। वहीं उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री लिखीराम की नक्सलियों की ओर से हत्या किए जाने पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि आज कांग्रेसी खामोश हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री की हत्या का बदला उनकी सरकार ने लिया। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी का तीन बार नाम लिया। क्रमपूर्व पदोन्नति में शामिल जवानों को मुख्यमंत्री ने फीता काटकर सम्मानित किया।

60 जवानों को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन प्रदान

60 हॉकफोर्स जवानों को क्रमपूर्व पदोन्नति के साथ ही 10 परिवारों के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाएगी। यह वे 14 परिवार हैं जिन्होंने अपने परिजनों को नक्सली घटना में खोया है। जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के साथ हो नक्सली घटना में शहीद होने वाले आमजन के परिवार के 14 परिवारों को नौकरी का पत्र सौंपा। साथ ही बैगा महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आदिवासी टीमों और नक्सल में बेहतर काम करने वाले सीआरपीएफ को भी सीएम ने सम्मानित किया। इस अभियान में हॉक फोर्स के जवानों ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के मलाजखंड दलम के पांच सदस्यों रीता उर्फ तुब्बी, श्रीरांगु हिड़ामी उर्फ देवचंद, सुमन, ईमला उर्फ तुलसी और रवि मड़ावी उर्फ बदरे को मार गिराया था।

प्रसाद लेते समय मंदिर की छत गिरी तीन बच्चियों की मौत

● ग्वालियर।

एमपी के मुरैना जिले से बड़ी घटना सामने आई है। जहां अहरौली गांव में माता मंदिर की छत गिरने से तीन बच्चियों की मौत हो गई है। हादसा सोमवार की दोपहर का बताया जा रहा है।

दरअसल, गांव के रहने सतीश अपनी पत्नी के साथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए आए थे। प्रसाद देने के लिए उन्होंने बच्चियों को मंदिर के अंदर बुलाया। इसी दौरान छत की पटिया गिर गई और नीचे मौजूद बच्चियां मलबे में दब गईं। 4 अन्य बच्चियां और एक दंपती घायल हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू कार्य शुरु कर दिया था। मलबा हटाकर शवों को बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंच गई है। वहीं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुरैना जिले के अहरौली गांव में चामड़ माता के मंदिर की छत गिर गई। मलबे में दबकर 3 बच्चियों की मौत हो गई। हादसा 9 फरवरी सोमवार दोपहर करीब दो बजे मंदिर में गुंबद निर्माण के लिए पुरानी छत तोड़ते वक्त हुआ। गांव में ही रहने वाले सतीश गौड पत्नी पृथ्वी के साथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए थे। उन्होंने प्रसाद देने के लिए कुछ बच्चियों को भी मंदिर के भीतर बुला लिया। इसी दौरान पुरानी छत की पटिया गिर गई और नीचे बैठीं बच्चियां मलबे में दब गईं।

नरवणे की पुस्तक हुई लीक

● नई दिल्ली।

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की आगामी किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के कथित रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, इस पुस्तक को अभी संबंधित प्राधिकरणों से प्रकाशन की आवश्यक अनुमति नहीं मिली है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज फोरम पर ऐसी जानकारी सामने आई थी कि किताब की प्री-प्रिंट कॉपी इंटरनेट पर साझा की जा रही है। इन दावों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पाया गया कि 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' शीर्षक से टाइपसेट की गई एक पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। यह कॉपी कथित रूप से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पुस्तक का फाइनल कवर भी इस तरह प्रदर्शित किया गया है, मानो वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह मामला एक ऐसी पुस्तक के संभावित लीक या गोपनीयता उल्लंघन से जुड़ा है, जिसे अभी आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी है।

त्रिपोली, लेबनान। ढही हुई आवासीय इमारत के घटनास्थल पर मौजूद सैन्यकर्मी ।

नफ़रती भाषा ही हिंसा में बदलती है, इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई जरूरी

मानव अधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने सीएम सरमा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

● नई दिल्ली।

मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को दी एक शिकायत में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कराने की मांग की है। हर्ष मंदर का आरोप है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा संवैधानिक पद पर होते हुए देश की अल्पसंख्यक मुसलमान आबादी के खिलाफ नफ़रत भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।हर्ष मंदर के इन आरोपों के बाद एक सार्वजनिक बयान में हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि वह उनके खिलाफ सौ से अधिक एफ़आईआर दर्ज करवा देंगे। हाल के सालों में भारत में नफ़रत भरी भाषा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ बढ़ती हिंसा पर बहस तेज़ हुई है।सेंटर फॉर स्टडी ऑन हेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, साल 2025 में देशभर में 1,318 नफ़रती भाषणों की घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2024 के मुकाबले 13 प्रतिशत ज़्यादा है और 2023 के मुकाबले लगभग दोगुनी हैं।

इस रिपोर्ट के मुताबिक़ पिछले साल औसतन हर दिन चार नफ़रती भाषण हुए। इन घटनाओं का सबसे बड़ा निशाना धार्मिक अल्पसंख्यक, ख़ासतौर पर मुस्लिम और ईसाई समुदाय रहे।रिपोर्ट यह दावा भी करती है कि नफ़रत अब सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक निरंतर और संगठित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनती जा रही है।इस रिपोर्ट के मुताबिक़, लव जिहाद, लैंड

जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद जैसे साज़िशी नैरेटिव्स, हिंसा के खुले आह्वान, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार और धार्मिक स्थलों को तोड़ने की मांगें, सार्वजनिक मंचों से सामान्य रूप से कही जा रही हैं। ख़ास बात यह है कि ऐसी 88 प्रतिशत घटनाएं उन राज्यों में दर्ज हुईं जहां बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियां सत्ता में हैं,

जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन भाषणों को बड़े पैमाने पर फैलाने का माध्यम बने।इसी बीच, मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के कुछ बयानों को 'नफ़रत भरा' बताते हुए दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर अभी एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक अभिषेक साहू द्वारा राजा आफसेट 863/9 नेहरु नगर इंदौर से मुद्रित एवं युग प्रभात कार्यालय 10 प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित,सम्पादक अभिषेक साहू
मो. नं. 9920999817, भारत सरकार समाचार पत्र पंजीयन संख्या - 38189/72, डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/58/2024-2026 Yugindore@gmail.com